लखनऊ

शनिवार 7 फरवरी, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 168

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

"अपनी जिंदगी में अगर वाकई कुछ हासिल करना है तो, अपने तरीकों को बदलों अपने इरादों को कभी नहीं।"

TODAY WEATHER

DAY 20° Hi

NIGHT 10° Low

संक्षेप

आप की सरकार में कानून राज नहीं, गैंगस्टर राज है : जयवीर शेरगिल

जालंधर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि एक और दिन, एक और हत्या — जालंधर, पंजाब में एक गुरुद्वारे के बाहर आम आदमी पार्टी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह एक बार फिर र्रक्क सरकार के तहत कानून-व्यवस्था के पूरी तरह चरमराने को उजागर करता है। उन्होंने कहा, पंजाब में अब हत्या और रंगदारी आम बात हो गई है। र्रक्क सरकार के तहत कानून-व्यवस्था अपराधियों और गैंगस्टरों के हाथों में एक खिलौना बनकर रह गई है। विकास करने के बजाय र्रक्क ने पंजाब को गैंगस्टरों का खेल का मैदान बना दिया है। शेरगिल ने कहा कि गायक, व्यापारी, राजनेता, नौकरीपेशा वर्ग, कबड्डी खिलाड़ी — समाज का हर वर्ग संगठित अपराध का आसान शिकार बन गया है। उन्होंने कहा, पुलिस मशीनरी मीडिया की आवाज़ दबाने, राजनीतिक विरोधियों पर झूठे और मनगढ़ंत केस दर्ज करने, आलोचकों को डराने और अरविंद केजरीवाल व र्रक्क नेताओं को सुरक्षा कवच देने में व्यस्त है, जबकि आम पंजाबी गैंगस्टरों के रहमोकरम पर छोड़ दिए गए हैं। शेरगिल ने कहा कि र्रक्क के सत्ता में आने के बाद अपराध में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि सरकार ने राजनीतिक संरक्षण, कमजोर पुलिसिंग, चयनात्मक कार्रवाई और शून्य जवाबदेही का स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा, गैंगस्टरों और अपराधियों का हौसला इसलिए बढ़ा है क्योंकि उन्हें एक भ्रमित, दिशाहीन और राजनीतिक रूप से समझौता की हुई सरकार दिखाई दे रही है। जब अपराधियों को तुरंत सजा नहीं मिलती, पुलिस अधिकारियों का मनोबल टूटता है और राजनीतिक हस्तक्षेप जांच में होता है, तो अपराध अपने आप फलता-फूलता है।

भारत-नेपाल सीमा पर खुशियां मातम में बदलीं, बारात की बस 150 मीटर गहरी खाई में गिरी, 13 लोगों की दर्दनाक मौत

नई दिल्ली। भारत-नेपाल सीमा से सटे नेपाल के बैतडी जिले में गुरुवार की रात एक हृदयविदारक हादसा हुआ, जिसने शादी की खुशियों को चीख-पुकार में बदल दिया। बैतडी से बजांग जा रही बरातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण दुर्घटना में 13 बरातियों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 34 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसा गुरुवार की रात उस वक्त हुआ जब बस बैतडी के पुरचुंणी नगरपालिका-7 स्थित भवने गांव से दुल्हन लेकर विदा हुई थी और बजांग के सुनकुडा जा रही थी। रास्ते में पुरचूंणी के बड़गांव मोड़ के पास एक तीखी चढ़ाई और घुमाव पर बस का संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते बस सड़क से फिसलकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। रात का समय होने के कारण वहां अफरा-तफरी मच गई। जिला प्रहरी कार्यालय बैतडी के प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक बलदेव बडू ने बताया कि सूचना मिलते ही नेपाल एपीएफ, पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने अंधेरे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों को खाई से बाहर निकाला।

वेब सीरीज घूसखोर पंडत के खिलाफ ब्राह्मणों का प्रदर्शन, योगी ने लिया सख्त एक्शन, निर्माता-निर्देशक पर करवाई एफआईआर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। वेब सीरीज घूसखोर पंडत को लेकर बढ़ते विवाद के बीच लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस वेब सीरीज के निर्देशक और निर्माण दल के कई सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है। शिकायत में कहा गया है कि वेब सीरीज की विषयवस्तु और विशेषकर उसका नाम जन भावनाओं को आहत करता है और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है। प्रशासन ने सीधे कानूनी कदम उठाकर साफ कर दिया है कि जन असंतोष को नजरअंदाज नहीं किया जायेगा।

पुलिस के अनुसार बीते दिनों वेब सीरीज के नाम को लेकर कई शिकायतें मिलीं। कुछ वर्गों ने कहा कि घूसखोर शब्द को पंडत जैसे शब्द के साथ जोड़ना पूरे पंडित समाज पर कीचड़ उछालने जैसा है। इससे रोष और अशांति फैल सकती है। इन शिकायतों के बाद हजरतगंज के निरीक्षक विक्रम सिंह ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए मामला आगे बढ़ाया। प्राथमिकी में निर्देशक और निर्माण से जुडे कई लोगों के नाम शामिल किये गये हैं।

हम आपको बता दें कि इस मामले ने तब और जोर पकड़ा जब यह जानकारी सामने आयी कि मुख्यमंत्री ने खुद कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये। शासन का संदेश साफ है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर समाज को भड़काने की छूट नहीं दी जा सकती। उधर, विवाद बढ़ने पर निर्देशक नीरज पांडे ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यह एक काल्पनिक पुलिस कथा है और पंडत शब्द केवल एक काल्पनिक चरित्र का बोली में प्रचलित नाम है। उनका दावा है कि कहानी किसी जाति, धर्म या समुदाय पर टिप्पणी नहीं करती, बल्कि एक व्यक्ति के कर्म पर केंद्रित है। उन्होंने यह भी कहा कि एक रचनाकार के रूप में वह जिम्मेदारी और सम्मान का ध्यान रखते हैं। इस बीच, लगातार बढ़ते विरोध के बीच निर्माण दल ने फिलहाल सारी प्रचार सामग्री हटा लेने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि वेब सीरीज को पूरी कहानी के संदर्भ में समझा जाना चाहिये, न कि छोटी झलक के आधार पर परखा जाना चाहिये। उन्होंने भरोसा जताया कि शीघ्र ही दर्शकों के सामने पूरी वेब सीरीज पेश की जायेगी। इस बीच वेब सीरिज निर्माता संघ ने भी आपत्ति जताते हुए सूचना जारी की है कि शीर्षक के लिये जरूरी अनुमति नहीं ली गयी। संघ के अनुसार उद्योग के नियमों के तहत नाम की स्वीकृति अनिवार्य है और उसका पालन नहीं किया गया।

यूजीसी के बाद अब फिल्म विवाद में ब्राह्मणों के साथ खुलकर आईं मायावती, 'घूसखोर पंडत' पर बैन की मांग

फिल्म घूसखोर पंडत रिलीज से पहले ही विवादों में घिर चुकी है। फिल्म का नाम सामने आने के बाद से ही इसका जमकर विरोध हो रहा है। फिल्म के टाइटल को लेकर ब्राह्मण समाज ने आपत्ति जताई है। इसको लेकर लखनऊ में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं पूरे मामले पर फिल्म डायरेक्टर नीरज पांडेय की सफाई भी सामने आई है। अब यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने भी इस फिल्म पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म पर बैन लगाने की भी मांग की है। पूर्व सीएम मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह बड़े दुख व चिन्ता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यू.पी। में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में जो उनका अपमान व अनादर किया जा रहा है तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। उन्होंने आगे कहा कि इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है।

'जनता ने खारिज कर दिया तो राहत पाने अदालत चले आए', CJI की प्रशांत किशोर की पार्टी को फटकार

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जन सुराज पार्टी की उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती दी गई थी। प्रशांत किशोर की पार्टी ने राज्य में फिर से चुनाव कराने की मांग की थी। पार्टी का आरोप था कि सरकार ने वोटरों को लुभाने के लिए कल्याणकारी योजना का गलत इस्तेमाल किया है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिका में कहा गया था कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री महिला

रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये भेजे गए। पार्टी के मुताबिक यह आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कड़ी टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने पूछा, 'आपकी पार्टी को कितने वोट मिले? जब जनता नकार देती है, तो आप लोकप्रियता पाने के लिए अदालत का सहारा लेते हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह पार्टी सत्ता में आती, तो शायद वह भी यही काम करती। कोर्ट ने साफ किया कि किसी राजनीतिक दल के कहने पर पूरे राज्य का चुनाव रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके लिए हर उम्मीदवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के ठोस और अलग आरोप होने चाहिए। कोर्ट ने सीनियर वकील सी यू सिंह से कहा कि यह मामला एक राज्य से जुड़ा है, इसलिए उन्हें पटना हाई कोर्ट जाना चाहिए।

जन सुराज का नहीं खुला था खाता

बिहार चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर सत्ता बचाई थी। वहीं इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिली थीं, जबकि जन सुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और उसके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी।

क्या है जन सुराज का आरोप?

याचिका में आरोप लगाया गया कि कर्ज में डूबे राज्य ने चुनाव से ठीक पहले 15,600 करोड़ रुपये बांटे। इससे दूसरी पार्टियों को बराबरी का मौका नहीं मिला। पार्टी ने संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत कार्रवाई की मांग की थी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की मदद दी जाती है।

परीक्षा पे चर्चा : छात्रों से बोले प्रधानमंत्री मोदी- सिर्फ अंकों पर नहीं, जीवन को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दें

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छात्रों को अपने जीवन एवं शैक्षणिक कौशल को निखारने पर ध्यान केंद्रित की सलाह देते हुए शुक्रवार को कहा कि देश में डेटा सस्ता होने का मतलब यह नहीं है कि वे इंटरनेट पर समय बर्बाद करें। प्रधानमंत्री मोदी ने 'परीक्षा पे चर्चा 2026' के नौवें संस्करण में छात्रों से कहा कि शिक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए और सभी को पूरी लगन से पढ़ना चाहिए क्योंकि आधे-अधूरे मन से की गई पढ़ाई जीवन को सफल नहीं बनाती।

उन्होंने यहां अपने आवास पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए विद्यार्थियों के एक समूह से कहा, "हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच के भीतर हो लेकिन आसानी से प्राप्त होने वाला न हो। पहले मन को साधो, फिर मन को जोड़ो और फिर

जिन विषयों की पढ़ाई करनी है, उन्हें सामने रखो। तब आप हमेशा छात्र को सफल पाएंगे।"

मोदी ने छात्रों को मनोरंजन के लिए गेम खेलने में समय बर्बाद नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, "आपकी गेमिंग में रुचि है लेकिन भारत में डेटा सस्ता है तो सिर्फ समय काटने के लिए इसमें लिप्त मत होइए। इसे मनोरंजन के लिए मत करिए। जो लोग पैसे कमाने के लिए गेमिंग में लिप्त होते हैं, उनका ही नुकसान होता है। हमें देश में जुए को बढ़ावा नहीं देना है। मैंने ऑनलाइन जुए के खिलाफ कानून बनाया है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि गेमिंग एक कौशल है क्योंकि इसमें काफी गति होती है और इसका उपयोग सतर्कता परखने तथा आत्म-विकास के लिए किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हर किसी का कार्य करने का अपना अलग तरीका या शैली होती है। उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं। फिर भी, लोग मुझे सलाह देते हैं कि अलग तरीके से काम करो लेकिन हर किसी की अपनी कार्य-शैली होती है। कुछ लोग सुबह बेहतर पढ़ते हैं, कुछ रात में। जो भी आपको सही लगे, उस पर विश्वास करें लेकिन सलाह भी लें और अगर उससे आपको फायदा हो, तो ही उसे अपनी जीवनशैली में शामिल करें।"

फर्जी नंबर प्लेट मामले में स्वामी चैतन्यानंद को मिली जमानत, लेकिन अभी भी जेल में ही रहेंगे

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित जिला अदालत ने फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगाने के मामले में आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। हालांकि, इस जमानत के मिलने के बावजूद स्वामी चैतन्यानंद को अभी जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा, क्योंकि उन पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला भी दर्ज है। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर कड़े सवाल उठाए और जांच को बेहद लापरवाह करार दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेश कुमार ने सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की है, वह बहुत ही गैर-गंभीर (कैजुअल) तरीके से तैयार की गई है।

दुष्कर्म पीड़िता की गर्भपात की गुहार : महिला की मर्जी के बिना उसे मां बनने को मजबूर नहीं कर सकते- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की एक 18 साल की यौन उत्पीड़न पीड़िता युवती के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उसे 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने की अनुमति दे दी है। यह युवती तब गर्भवती हुई थी जब वह नाबालिग थी। जस्टिस बी.वी। नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि युवती की शारीरिक अखंडता और अपनी मर्जी से फैसला लेने का अधिकार सबसे ऊपर है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी अदालत किसी महिला को अनचाही प्रेग्नेंसी जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जजों ने कहा कि अगर कोई महिला बच्चा नहीं चाहती, तो उसे इसके लिए बाध्य करना गलत होगा। बेंच ने युवती के

वकील की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा अपीलकर्ता के बच्चे का मेडिकल तरीके से गर्भपात किया जा सकता है।'

फैसला लेना आसान नहीं था

सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने इस मामले की गंभीरता और नैतिक उलझनों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह फैसला लेना उनके लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि जन्म लेने वाला बच्चा भी एक जीवन ही होता। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जब लड़की बार-बार कह रही है कि वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, तो उसकी इच्छा का सम्मान करना होगा। अदालत ने सवाल किया कि अगर कानून 24 हफ्ते तक गर्भपात की इजाजत देता है, तो विशेष परिस्थितियों में 30 हफ्ते में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?

अदालत ने अस्पताल को दिया आदेश

बेंच ने यह भी साफ किया कि मुद्दा यह नहीं है कि संबंध सहमति से बने थे या यह उत्पीड़न का मामला था। मुख्य तथ्य यह है कि होने वाला बच्चा वैध नहीं है और दूसरा, लड़की इस समय एक कठिन स्थिति में है और वह मां नहीं बनना चाहती। अगर मां के हितों को ध्यान में रखना है, तो उसे मर्जी से फैसला लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के जेजे अस्पताल को आदेश दिया है कि वे लड़की की गर्भपात को मेडिकल तरीके से खत्म करें। साथ ही, अस्पताल को सभी जरूरी सुरक्षा नियमों और मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली दंगा मामला : आरोपियों की जमानत पर नोटिस जारी, पुलिस से मांगी स्थिति रिपोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट और राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण आदेश पारित किए गए हैं, जिनसे दंगों की कथित साजिश और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों पर नया मोड़ आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी सामिल मलिक, अतहर खान और मोहसिन की जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। साथ ही, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह इन आरोपियों की भूमिका को लेकर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिकाओं पर विचार से पहले आरोपियों की भूमिका, जांच की प्रगति और उपलब्ध सबूतों की स्थिति को समझना जरूरी है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को निर्धारित की गई है। वहीं, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान जबरन राष्ट्रगान गाने से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों को समन जारी किया है। यह मामला फैजान नामक युवक से जुड़ा है, जिस पर आरोप है कि दंगों के दौरान उसे कथित तौर पर पुलिसकर्मियों ने पीटा और जबरन राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया। इस प्रकरण में अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने आरोपियों को 24 फरवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

एनसीआर में सुबह-शाम तेज हवाओं और दिन में धूप ने बढ़ाई परेशानी ; एक्यूआई में आंशिक सुधार

नोएडा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इन दिनों मौसम लगातार करवट बदल रहा है। सुबह और शाम के समय तेज ठंडी हवाओं के कारण गलन बढ़ गई है, जबकि दिन निकलते ही तेज धूप और बढ़ता तापमान लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। मौसम के इस दोहरे प्रभाव से आमजन सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं।

अस्पतालों और निजी क्लीनिकों में मौसम से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में लगभग 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, एनसीआर में आने वाले दिनों में सुबह के समय कोहरा बना रह सकता है। मौसम विभाग की वेबसाइट पर जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 6 फरवरी को अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दिन आर्द्रता 95 से 55 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई है और हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। 7 फरवरी को तापमान 24 और 11 डिग्री, जबकि 8 फरवरी को 23 और 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। 8 फरवरी को मॉडरेट फॉग यानी मध्यम स्तर का कोहरा छाने का पूर्वानुमान है।

हालांकि इन दिनों मौसम को लेकर फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। तेज हवाओं का असर वायु गुणवत्ता पर भी देखने को मिला है। हवा चलने से प्रदूषक कणों का फैलाव हुआ, जिससे एक्यूआई में आंशिक सुधार दर्ज किया गया।

उत्तर प्रदेश में एसआईआर की मियाद फिर बढ़ी, अब 10 अप्रैल को जारी होगा फाइनल वोटर लिस्ट

आर्यावर्त क्रांति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के लिए जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से तारीख बढ़ा दी गई है। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने आज शुक्रवार को एसआईआर प्रक्रिया को लेकर तारीख बढ़ाने का ऐलान करते हुए बताया कि इसे एक और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका कहना है कि एसआईआर को लेकर कई दल तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब 10 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।

मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा ने आज बताया कि उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर दावे और आपत्ति

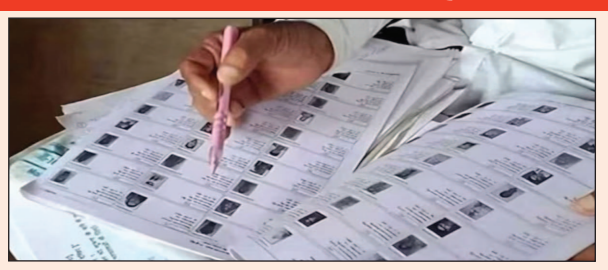

करने की तारीख फिर से बढ़ा दी गई है। इसे एक और महीने के लिए बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि 5 फरवरी तक 82,684 फॉर्म-7 तो 37,80,414 फॉर्म-6 को 6 जनवरी से 4 फरवरी तक जमा कराया गया है। इसी तरह से 1073 ओवरसीज से एप्लीकेशन आए हैं। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक फॉर्म्स 5 फरवरी को जमा कराए गए, इस दिन 3 लाख से ज्यादा फॉर्म्स आए।

एसआईआर की मियाद बढ़ाए जाने को लेकर नवदीप रिणवा ने बताया कि 27 जनवरी को राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में तारीख फिर से बढ़ाने की मांग आई थी और सभी इस पर सहमत थे कि समय बढ़ाया जाना चाहिए। इसीलिए इसमें एक महीने का समय बढ़ाया गया है।

उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियों का समय एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नोटिस का जवाब और सत्यापन के लिए एक महीना का वक्त बढ़ाया गया है। अब 6 मार्च तक फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 जमा करवा सकते हैं। नोटिस के सुनवाई की प्रक्रिया 27 मार्च तक चलेगी। 27 मार्च तक मैपिंग करवाया जा सकेगा और नोटिस का जवाब दे सकेंगे। जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 10 अप्रैल को प्रकाशित होगी।

ड्रॉफ्ट लिस्ट में 12.55 करोड़ से अधिक वोटर्स

चुनाव आयोग की ओर जारी आंकड़ों में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के तहत अब तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में वोटर्स की संख्या 12,55,56,025 थी। इसमें Form 6 की संख्या 54,37,850 थी तो फॉर्म 7 की संख्या 1,33,650 रही। BLAs की ओर से जमा किए गए फॉर्म 6 की संख्या 37,789 रही तो आम नागरिकों की ओर से जमा किए गए फॉर्म 6 और 6A की संख्या 37,81,487 थी। ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद जमा कराए गए फॉर्म 6 की कुल संख्या 38,19,276 थी तो ड्राफ्ट जारी होने से पहले जमा कराए गए फॉर्म 6 की संख्या 16,18,574 थी। 4 फरवरी तक कुल फॉर्म 6 की संख्या 54,37,850 थी।

कानून का सम्यक ज्ञान और कोर्ट रूम में जाकर प्रैक्टिस करना दो अलग बाते: डॉ. ए के सिंह

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। कानून का सम्यक ज्ञान और कोर्ट रूम में जाकर प्रैक्टिस करना दो अलग बातें हैं। फिर भी कानूनी ज्ञान मनुष्य की समझ को बढ़ाता है और परिष्कृत करता है। जनपद ही नहीं पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर ए के सिंह ने बताया कि अभी हमने कानून की परीक्षा पास किया है। मेरा मानना है कि कानून का ज्ञान हर नागरिक के लिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें अधिकारों / कर्तव्यों / समाज में सही आचरण की समझ आती है। अन्याय या भेदभाव होने पर क्या करना है, पुलिस या प्रशासन की सीमा क्या है। अपने कर्तव्यों को समझना दूसरे के अधिकारों का सम्मान, देश के कानूनों का पालन, लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए एवं जिम्मेदार नागरिकों को गलत कार्य करने से रोकती है। दंड के परिणाम समझाती है और समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहायक है।

अतः कानून का ज्ञान व्यक्ति को जागरूक सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनाता है, कानून हमें अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों की बात भी सिखाता है। कोविड की दूसरी लहर जिसमें कि हर व्यक्ति को ऑनलाइन स्टडीज, कॉन्फ्रेंस सुनने और एक ही जगह सीमित कर दिया गया था। उस समय का उपयोग मन में आया कि एलएलबी किया जाय, इसमें सर्वप्रथम मैंने केएनआई के प्राचार्य लॉ विभाग में कार्यरत हैं, उनसे मिला समझा पुस्तकों का संकलन और फॉर्म भरने के लिए राम मनोहर लोहिया अवध विश्व विद्यालय अयोध्या से ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई करते हुए सोचा कि जिस सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो जाऊंगा वहीं से पढ़ाई छोड़ दूंगा। पढ़ाई और परीक्षा देते गए रेगुलर कोई बाधा नहीं आयी।

अधिकतर मेरी पढ़ाई यूट्यूब से हुई, मोटी किताबें पढ़ना छोड़ दिया एल एल बी की, परीक्षा पास करने के बाद मन में था कि एआईबीई की परीक्षा पास करनी है।

जो कि नवंबर में हुई 30 नवंबर 2025, यह मेरी पहली परीक्षा थी जो कि किताबों के साथ हुई। 30 नवंबर पढ़ते समय AIBE की तैयारी के समय यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया हुआ पढ़ा, कि कैसे पास कर सकते है प्रश्न निश्चित रूप से सरल नहीं थे (इतने कठिन भी नहीं थे) रणनीतिक मैंने शुरू में जो सही से मुझे प्रश्न आते थे उनको कोशिश करते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका साथ-साथ भरा। फिर जो प्रश्न पतली पुस्तकों में थे उनको किया और अंत में निरीक्षक जो परीक्षा हाल में रक्षक कर रहे थे बोले की माइनस मार्किंग नहीं है। फिर सारे शत-प्रतिशत प्रश्न प्रयास किया और परीक्षा पूरी करके बैठ गया ए आई बी ई के परीक्षाफल का इंतजार करता रहा, जो की 30 नवंबर 2025 को हुई थी। 07 जनवरी 2026 को परीक्षाफल आ गया और लगभग 02 लाख 69 हजार के आसपास परीक्षार्थी थे और 69.1% रिजल्ट आया उसमें से मैं भी पास हुआ।

डायग्नोस्टिक जांच में लापरवाही का आरोप, महिला की हालत गंभीर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच के दौरान कथित चिकित्सकीय लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुड़वार थाना क्षेत्र के ग्राम बेला पश्चिम निवासी अभिषेक त्रिपाठी ने नगर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर संबंधित डॉक्टर और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के अनुसार 26 जनवरी को वह अपनी पत्नी शीतल को लखनऊ स्थित आशा आयुर्वेद हॉस्पिटल ले गए थे। डॉक्टर की सलाह पर 31 जनवरी को सुलतानपुर के एक डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच कराई गई। आरोप है कि जांच के दौरान पैथोलॉजी डॉक्टर व स्टाफ ने लापरवाही बरतते हुए महिला के गर्भाशय में एक यंत्र डाल दिया,जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और वह कई घंटों तक असहनीय दर्द से तड़पती रही।महिला की हालत गंभीर होने पर उसे पहले हनुमत हॉस्पिटल रेफर किया गया,जहां डॉक्टरों ने बताया कि लापरवाही से उसकी जान जा सकती थी। इसके बाद परिजन महिला को तत्काल लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल ले गए। वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि जांच में हुई गंभीर चूक से महिला की जान खतरे में पड़ गई थी। लंबे इलाज और भारी खर्च के बाद महिला की जान बच सकी।पीड़ित ने पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नगर कोतवाल ने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है,जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बेटा प्रॉपर्टी डीलर, उन्नाव में 75 साल की मां की हत्या की क्या है वजह

आर्यावर्त संवाददाता

उन्नाव। गंगाघाट क्षेत्र के कंजाखेड़ा गांव में शुक्रवार दोपहर डेढ़ बजे नशे में राजन ने अपनी 75 वर्षीय मां शांति रावत की लोहे के पाइप से घर के बाहर वार कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित बेटा मौके से फरार हो गया।

गंगाघाट कोतवाल अजय कुमार सिंह ने जांच शुरू की और खून से सना लोहे का पाइप बरामद कर लिया। एएसपी अखिलेश सिंह और सीओ सिटी विनी सिंह ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं।

पुलिस स्वजन और क्षेत्रीय लोगों से पूछताछ कर रही है और फरार आरोपित की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि आरोपित प्रापर्टी डीलर है।

बाराबंकी में एसपी ने पुलसिकर्मियों की तैनाती में किया फेरबदल, 18 सब-इंस्पेक्टरों की तैनाती, तीन चौकी प्रभारी बदले

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बाराबंकी। पुलिसिंग को चुस्त-दुरुस्त और जवाबदेह बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने चौकी प्रभारियों पर कार्रवाई के साथ फेरबदल किए। तीन चौकी प्रभारियों से जिम्मेदारी हटा ली गई, जबकि एक चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। 18 उपनिरीक्षकों को विभिन्न थानों व चौकियों में नई तैनाती दी गई है।

देवा के चौकी मित्तई के प्रभारी अश्वनी कुमार सिंह को लापरवाही के चलते लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक रामकृपाल सिंह को सम्मन सेल प्रभारी बनाया गया है। निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी को अपराध शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जहांगीराबाद से निरीक्षक रामकृपाल चौहान को रामसनेहीघाट में अतिरिक्त निरीक्षक, एसएसआइ बदोसराय जय प्रकाश यादव को उसी थाने में अतिरिक्त निरीक्षक बनाया गया है।

पुलिस लाइन में तैनात 18 उपनिरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां दी गई है। अनुराग पाठक को चौकी प्रभारी सिविल लाइन, संतोष कुमार मौर्य को चौकी प्रभारी अहमदपुर, जगन्नाथमणि त्रिपाठी को चौकी प्रभारी मित्तई, उपेंद्र सिंह भदौरिया को चौकी प्रभारी लालपुर करौता बनाया गया है।

रजनीश कुमार पांडेय को थाना रामनगर, जितेंद्र सिंह को लोनीकटरा, जयलाल को थाना रामसनेहीघाट, भानू प्रताप शाही व वेद प्रकाश गुप्ता को टिकैतनगर, वीरेश पाल सिंह व राजकुमार यादव को जहांगीराबाद, मिथलेश चौहान को मसौली, राम बदन राम को असंद्रा, विशेष प्रताप सिंह व सुभाष चंद्र यादव को कोतवाली नगर, अभिषेक को थाना बदोसराय तथा अनुभव मिश्र को टिकैतनगर से बदोसराय भेजा गया है। कोतवाली नगर से सुधाकर यादव को एसएसआइ थाना कुर्सी भेजा गया है।

वंदे भारत ट्रेन में पथराव मामले का आया सीसीटीवी फुटेज ऑर रिकॉर्ड, नयापुरवा के पास की निकली घटना

आर्यावर्त संवाददाता

रायबरेली। वंदेभारत ट्रेन पर हुए पथराव की घटना को लेकर आरपीएफ की मांगे गए रिपोर्ट के आधार पर घटनास्थल शहर के नयापुरवा के पास का निकला है। आरपीएफ ने विवेचना शुरू शुक्रवार से कर दी है। बता दें कि सोमवार (दो फरवरी) की देर शाम प्रयागराज से गोरखपुर जा रही गाड़ी संख्या 22550 वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन में पत्थरबाजी की घटना हुई थी। इसको लेकर आरपीएफ ने वंदेभारत एक्सप्रेस के बोगी नंबर सी-6 के सीट नंबर 20 पर लगे सीसीटीवी फुटेज की मांग गोरखपुर से की गई थी।

आरपीएफ पोस्ट प्रभारी एके सिंह का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज शुक्रवार को आ गए हैं। इसके रिकार्ड के अनुसार रेलवे गेट नंबर 27 से दरियापुर के मध्य नयापुरवा पास की घटना निकला है। इसके आधार पर विवेचना आरपीएफ उप निरीक्षक नरसीराम गुर्जर को सौंपी गई है। फुटेज के बाद पर संदिग्ध की जांच जारी कर दी गई है। जल्द पत्थरबाजी करने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा।

मीरजापुर पहुंची पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अस्थि कलश यात्रा, अर्पित की गई श्रद्धांजलि

आर्यावर्त संवाददाता

मीरजापुर। विमान हादसे में निधन हुए महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार की अस्थि कलश यात्रा शुक्रवार को सड़क मार्ग से प्रदेश सीमा के भैसोड़ बलाय पहाड़ ड्रमंडगंज पहुंची। इस यात्रा के दौरान अस्थि कलश को काशी की ओर ले जाया जा रहा है। ड्रमंडगंज से होते हुए यह यात्रा विकास खंड पहाड़ी के भरपुरा पहुंची, जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी।

इस अवसर पर मां शारदा लान में पार्टी के नेता अरुण दुबे के साथ-साथ स्थानीय जनमानस ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और आम नागरिक शामिल थे, जिन्होंने अजित पवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

अजित पवार का निधन एक बड़े राजनीतिक क्षति के रूप में देखा जा रहा है। उनके योगदान और कार्यों को याद करते हुए उपस्थित लोगों ने उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस अस्थि कलश का विसर्जन काशी में शुक्रवार की शाम को किया गया, जहां उनके अनुयायी और समर्थक एकत्रित रहे।

अजित पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। उनकी अस्थि कलश यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, जो उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर नहीं छोड़ना चाहते थे।

इस यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले लोगों को कोई कठिनाई न हो। स्थानीय प्रशासन ने भी इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।मीरजापुर में अजित पवार की अस्थि कलश यात्रा ने एक भावुक माहौल का निर्माण किया, जिसमें सभी ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सख्ती

सुल्तानपुर। परिवहन विभाग ने मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट या थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं लगा होगा, उन पर किसी भी प्रकार की परिवहन संबंधी कार्यवाही नहीं की जाएगी। बिना HSRP वाले वाहनों के लिए स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, हाइपोथिकेशन पृष्ठांकन अथवा निरस्तीकरण, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट नवीनीकरण, अस्थायी परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट सहित बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र के अद्यतन जैसे किसी भी कार्य को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। परिवहन विभाग ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि सभी वाहन स्वामियों को अनिवार्य रूप से अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवानी होगी।

सीएम योगी तक पहुंची तहसीलों की शिकायत तो अफसरों में मची खलबली, मेरठ 9 तो गाजियाबाद 11 फरवरी . . . पूरा टाइम-टेबल जारी

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। तहसीलों में मनमानी और भ्रष्टाचार से आम जनता परेशान है। भाकियू संगठन बार बार विभिन्न तहसीलों पर इसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। यह शिकायतें अब मुख्यमंत्री तक जा पहुंची है। उनके निर्देश पर मुख्य सचिव ने सभी तहसील और सभी कलक्ट्रेट का समय समय पर निरीक्षण करने का आदेश कमिश्नर और डीएम को दिया है। ताकि यह मनमानी रोकी जा सके।

यह निरीक्षण फरवरी महीने में ही पूरे करके उसकी रिपोर्ट शासन को भेजनी होगी। जिसे मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने मंडल के सभी जनपदों के डीएम कार्यालय के निरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सबसे पहले 9 फरवरी को मेरठ जनपद का निरीक्षण होगा। जिसकी तैयारी में अधिकारी जुट गए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को सभी कलक्ट्रेट और तहसीलों का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। उन्होंने लिखा है कि निरीक्षण से आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सकेगा।

उन्होंने फरवरी महीने में विशेष अभियान चलाकर सभी तहसीलों और कलक्ट्रेट का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। निरीक्षण के लिए विशेष बिंदु भी उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। निरीक्षण की रिपोर्ट को संकलित करके मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

कमिश्नर ने जारी किया कार्यक्रम, डीएम जल्द करेंगे

मुख्य सचिव का आदेश मिलते ही मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने मंडल के सभी जनपदों के जिलाधिकारी कार्यालयों (कलक्ट्रेट) का निरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है। सबसे पहले 9 फरवरी को मेरठ में निरीक्षण होगा। 11 को गाजियाबाद, 12 को बुलंदशहर, 14 को बागपत, 20 फरवरी को हापुड़ तथा 26 फरवरी को गौतमबुद्धनगर में कलक्ट्रेट का निरीक्षण करेंगे।

माना जा रहा है कि डीएम भी जल्द तहसीलों के निरीक्षण का कार्यक्रम जारी करेंगे। वहीं कमिश्नर के निरीक्षण के लिए कलक्ट्रेट कर्मियों ने गुरुवार से ही तैयारी शुरू कर दी। एडीएम सिटी मे भी विभिन्न पटलों पर पहुंचकर तैयारी कराई।

इन बिंदुओं पर होगा निरीक्षण

तहसील परिसर में साफ सफाई और जनसुनिधाएं, राजस्व न्यायालयों में मामलों के निस्तारण की गति, अन्य प्रशासनिक कार्यों को शिकायतों के निस्तारण में लगने वाली अवधि का आकलन होगा। जबकि कलक्ट्रेट में जनसुविधाओं के साथ साथ राजस्व न्यायालयों में सुनवाई, राजस्व अभिलेखागार के अभिलेखों का रखरखाव और नकल आवेदनों का निस्तारण, चरित्र हैसियत, जाति समेत अन्य प्रमाण पत्रों को जारी करना, चरित्र सत्यापन का कार्य तहसील दिवस और आइजीआरएस के मामलों के निस्तारण की स्थिति, शस्त्र लिपिक पटल की कार्यप्रणाली।

गोरखपुर के नकहा स्टेशन के पास लगा रेलवे का धर्मकांटा, चलती मालगाड़ियों का ऑटोमेटिक हो जाएगा वजन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। नकहा जंगल रेलवे स्टेशन के पास गति शक्ति मल्टी माडल कार्गो टर्मिनल साइडिंग में रेलवे का धर्मकांटा लग गया है। इसके लिए रेलवे की पटरियों में 'इन मोशन वेब्रिज' लगाया गया है। खास बात यह है कि रेलवे के इस धर्मकांटा पर चलती हुई मालगाड़ियों का आटोमेटिक (स्वतः) वजन हो सकेगा।

वजन भी लगभग 100 प्रतिशत सटीक होगा। मालगाड़ियों में ओवरलोडिंग पर अंकुश तो लगेगा ही, ट्रेनों का निर्बाध संचालन हो सकेगा। समय की बचत होने से ट्रेनों का समय पालन दुरुस्त होगा।

हिंदुस्तान खाद कारखाना (एचयूआरएल), गोरखपुर से खाद की ढुलाई भी आसान हो जाएगी। खाद कारखाना से निकलने वाली खाद सहित सभी रेक का वजन चलती हुई मालगाड़ी में ही हो जाएगी। वजन का डेटा माल अधीक्षक में कंप्यूटर में प्रदर्शित होता रहेगा।

जानकारों के अनुसार रेल लाइनों पर लगा 'इन मोशन वेब्रिज' चलते समय ही मालगाड़ियों का वजन माप लेता है। जिससे ट्रेनों के रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोडिंग-अनलोडिंग सिस्टम की दक्षता बढ़ती है। 'इन मोशन वेब्रिज' यातायात और औद्योगिक प्रबंधन के लिए उपयोगी है। जिसमें रेलवे ट्रैक में लगे सेंसर एक्सल या कुल वजन को गतिशील रूप से माप लेता है।

'इन मोशन वेब्रिज' में रेल पटरी के नीचे सेंसर लगाए जाते हैं। ट्रेन के गुजरते समय सेंसर प्रत्येक पहिये व एक्सल पर वजन का पता लगाता है। 'इन मोशन वेब्रिज' का कंप्यूटराइज्ड सिस्टम सेंसर के माध्यम से प्रत्येक पहिये और एक्सल का वजन तथा वाहन के कुल वजन की गणना कर लेता है। आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर रेलवे में पड़ने वाले प्रमुख कारखानों व संबंधित स्थलों पर 'इन मोशन वेब्रिज' लगाए जाएंगे।

स्टेशन डायरेक्टर रतनदीप गुप्ता बताते हैं कि नकहा जंगल रेलवे स्टेशन के पास गति शक्ति मल्टी माडल कार्गो टर्मिनल साइडिंग की तरफ 'इन मोशन वेब्रिज' कार्य करने लगा है। खाद कारखाना से निकलने वाले सभी रेक का वजन चलती हुई मालगाड़ी में हो जा रहा। बिना रुके गाड़ियों का वजन हो जा रहा। ट्रेनों का संचालन निर्बाध गति से हो रहा है।

15 फरवरी तक चलेगा मध्यस्थता अभियान 2.0

सुलतानपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर तथा जनपद न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जनपद सुलतानपुर में मध्यस्थता अभियान 2.0 संचालित किया जा रहा है। यह अभियान 01 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक चलेगा, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में लंबित मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से कराया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुलतानपुर के सचिव मुक्ता त्यागी ने बताया कि अभियान के तहत मध्यस्थता योग्य वादों को चिन्हित कर संबंधित पक्षकारों को संदर्भित किया जा रहा है। जनपद की समस्त न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों से भी ऐसे मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान हो सके। सचिव ने बताया कि अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

सेवा संघ ने 453 जरूरतमंदों को कराया नि :शुल्क भोजन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

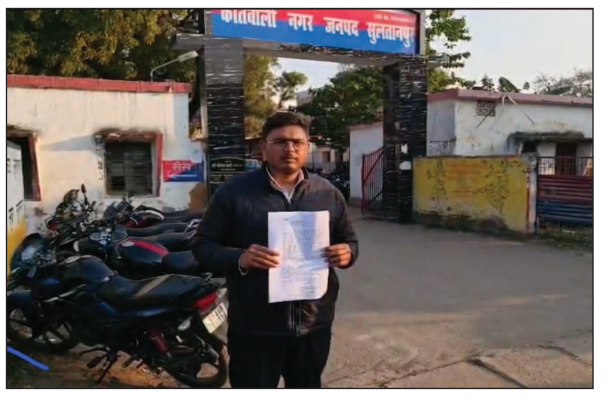

सुल्तानपुर। जिले के अग्रणी सामाजिक संगठन राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ द्वारा बृहस्पतिवार देर रात स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जिला चिकित्सालय तथा रेलवे स्टेशन परिसर में निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मरीजों, उनके तीमारदारों, यात्रियों एवं अन्य जरूरतमंदों सहित कुल 453 लोगों को गरम ताज़ा भोजन उपलब्ध कराया गया।

कार्यक्रम का आयोजन संगठन के अध्यक्ष मेराज अहमद खान के नेतृत्व में संपन्न हुआ। रेलवे स्टेशन परिसर में वरिष्ठ टिकट निरीक्षक अभिषेक अवस्थी ने जरूरतमंद को भोजन की थाली प्रदान कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

संगठन के सदस्य निजाम खान ने बताया कि स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की थाली में अरहर की दाल, मौसमी सब्जी, रोटी और चावल शामिल रहे। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय परिसर में 290 तथा रेलवे स्टेशन परिसर में 163 लोगों को भोजन वितरित किया गया। भोजन वितरण कार्यक्रम में नफीसा बानो, हाजी फैज उल्लाह अंसारी, सरदार गुरुप्रीत सिंह, अब्दुल वदूद (मिलियन टेलर), लईक अहमद, राकेश कुमार शुक्ला, इश्तियाक अहमद, सूफियान खान, यूसुफ पठान, बैजनाथ प्रजापति, माता प्रसाद जायसवाल आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

विरासत के सम्मान से सुरक्षित हुई बेटियां, सशक्त हुआ व्यापारी, यूपी बना विकास और सुशासन का मॉडल: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा था, जब देश की महान विरासत को कोसा जाता था, उसे अपमानित और लांछित किया जाता था। राम भक्तों पर गोलियां चलती थीं और यह केवल किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अपमान था। इसके दुष्परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश अराजकता, लूट और दंगों का अड्डा बन गया था। गुंडागर्दी चरम पर थी, न बेटियां सुरक्षित थीं और न ही व्यापारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उनकी सरकार में विरासत को सम्मान मिला, तो प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण बना, बेटियां सुरक्षित हुईं और व्यापारियों को भी निर्भय माहौल मिला। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को हरिद्वार में आयोजित स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज की श्री विग्रह मूर्ति स्थापना समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में न अराजकता है, न फसाद, न गुंडागर्दी। न कर्फ्यू है, न दंगे हैं। यूपी में अब सब चंगा है। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो चुके हैं और कर्फ्यू अब दंगाइयों पर लगता है। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरकार की नीति स्पष्ट और नीयत साफ रही। उन्होंने कहा कि क्या कोई कल्पना कर सकता था कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन आज वह सपना साकार हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि बिना किसी औपचारिक प्रशासनिक अनुभव के वह उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को कैसे चला रहे हैं। इस पर उनका उत्तर होता है कि वह आश्रम व्यवस्था से जुड़े रहे हैं। प्रशासन और प्रबंधन का वास्तविक ज्ञान भारतीय आश्रम पद्धति से ही मिलता है। भारत का संन्यासी आश्रम परंपरा से ही नेतृत्व और अनुशासन सीखता है। प्रशासन हमारे संस्कारों और जींस का हिस्सा है। एमबीए की वास्तविक शिक्षा भारतीय आश्रम पद्धति में निहित है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश आज अराजकता से निकलकर विकास और सुशासन का एक प्रभावी मॉडल बनकर उभरा है। भारत की शक्ति की जड़ें आश्रम और गुरुकुल परंपरा में रही हैं, जहां कृषि, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, शिल्प और प्रशासन जैसे विषयों का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता था।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले का उल्लेख करते हुए बताया कि अब तक 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जहां पहले अव्यवस्था दिखाई देती थी, वहीं आज अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन, प्रयागराज, हरिद्वार, बदरीनाथ धाम और केदारनाथ धाम केवल आस्था के केंद्र नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के केंद्र बन चुके हैं। भारत को शक्ति इन्हीं आस्था स्थलों से मिलती है। जब इन केंद्रों को सम्मान और संरक्षण मिला, तो उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। लंबे समय तक बीमारू राज्य कहलाने वाला उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था के लिए ब्रेकथ्रू बनकर निरंतर प्रगति कर रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जन्म देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। वर्ष 1982 में भारत माता मंदिर के भव्य लोकार्पण का आयोजन हुआ था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सर संघचालक बालासाहब देवरस की उपस्थिति रही थी। यह इस बात का प्रतीक था कि राष्ट्र के प्रति सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन मूल्यों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। विपरीत परिस्थितियों में भी स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज ने भारत माता मंदिर के निर्माण के माध्यम से देश को आध्यात्मिक नेतृत्व का स्थायी स्मारक दिया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड के चार धाम भारत की चेतना के आधार स्तंभ हैं। हरिद्वार आते समय बचपन से ही मन में हरि की पैड़ी में स्नान और भारत माता मंदिर के दर्शन की भावना रहती थी। यहां न जाति का भेद था और न धर्म का कोई अंतर। भारत माता मंदिर में पूरे देश का स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश ने व्यापक परिवर्तन देखा है। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज से लेकर केदारपुरी, बदरीनाथ और हरिद्वार तक विकास की एक लंबी गाथा विरासत को संजोते हुए आगे बढ़ी है। यह नए भारत के निर्माण की वही गाथा है, जिसका इंतजार वर्तमान पीढ़ी सदियों से कर रही थी।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि ऋषि परंपरा की तपस्या से निर्मित एक राष्ट्र है। भारत की आत्मा धर्म में निहित है और जहां धर्म है, वहीं विजय है। इतिहास गवाह है कि जो राष्ट्र अपनी सभ्यता और संस्कृति की उपेक्षा करता है, वह न वर्तमान को सुधार सकता है और न भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। वैदिक भारत आत्मनिर्भर सभ्यता का प्रतीक रहा है। आक्रांताओं के आने से पहले भारत एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र था, जिसकी नींव ऋषियों की तपस्या, किसानों के श्रम और कारीगरों की सृजनशीलता पर टिकी थी।मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 44 प्रतिशत तक रही और 400 वर्ष पहले भी यह 25 प्रतिशत थी। यह सामर्थ्य हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और आत्मनिर्भर व्यवस्था का परिणाम था। जैसे ही हम इन मूल्यों से दूर हुए, पतन शुरू हो गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फिर से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है।

आवारा कुत्तों की समस्या पर योगी सरकार सख्त : जन सुरक्षा के लिए प्रदेशभर में डॉग शेल्टर होम और एबीसी सेंटर की स्थापना तेज

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और डॉग बाइट की लगातार सामने आ रही घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने जन सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर ठोस और निर्णायक कदम उठाए हैं। आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने नगर निगमों एवं जनपद मुख्यालयों पर डॉग शेल्टर होम तथा एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। शासन स्तर पर इस योजना को प्राथमिकता देते हुए भूमि चिह्नीकरण, बजट निर्धारण और परियोजना स्वीकृति की कार्रवाई एक साथ आगे बढ़ाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस विषय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान मानवीय, वैज्ञानिक और स्थायी तरीके से किया जाए। सरकार का मानना है कि डॉग शेल्टर होम और एबीसी सेंटर की प्रभावी और सुव्यवस्थित व्यवस्था से जहां एक ओर आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर पशु कल्याण को भी मजबूती मिलेगी। यही कारण है कि इस योजना को केवल अस्थायी समाधान नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नीति के रूप में लागू किया जा रहा है।

भाजपा की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का आह्वान

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस (मध्य जोन) के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों के मनोनयन-पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान कांग्रेस (मध्य जोन) के पूर्व अध्यक्ष जगदीश सिंह ने की। इस अवसर पर किसान कांग्रेस (मध्य जोन) के अध्यक्ष बृज मौर्या एवं प्रदेश उपाध्यक्ष/प्रभारी संगठन सर्वेश श्रीवास्तव द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कांग्रेस सूचना का अधिकार विभाग के चेयरमैन पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव, कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉ. अमित कुमार राय तथा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अनामिका यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय बहादुर एवं सुरेन्द्र कुमार की गरिमामयी उपस्थिति भी रही।मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए मनीष हिंदवी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भाजपा सरकारों ने यदि किसी वर्ग पर सबसे अधिक अन्याय किया है, तो वह किसान हैं। उन्होंने कहा कि न तो किसानों के लिए कोई ठोस और सार्थक नीति बनाई गई और न ही उनकी जमीनी समस्याओं के समाधान के लिए कोई गंभीर प्रयास किए गए। क्रोनी पूंजीवाद के सहारे चल रही भाजपा सरकार किसानों के प्रति इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि उसने अमेरिका के दबाव में देश का कृषि बाजार भी उनके लिए खोल दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस फैसले का आने वाले समय में किसानों पर कितना गंभीर और विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, इसकी कल्पना करना भी कठिन है।मनीष हिंदवी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से कहा कि मनोनयन पत्र केवल एक कागज नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और संघर्ष के साथ निभाना होगा। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार की तानाशाही और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जननायक राहुल गांधी के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चलना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे किसान कांग्रेस (मध्य जोन) के पूर्व अध्यक्ष जगदीश सिंह ने किसान कांग्रेस (मध्य जोन) के अध्यक्ष बृज मौर्या को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में किसान कांग्रेस एक नए और सशक्त अध्याय की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में किसानों के प्रति जिस तरह की उदासीनता देखने को मिल रही है, ऐसे में किसान कांग्रेस की लड़ाई और अधिक कठिन तथा संघर्षपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि चाहे खाद का संकट हो, मनरेगा की बदहाली हो, गन्ने की कीमतों का मुद्दा हो या किसानों को मुफ्त बिजली देने का सवाल—इनमें से कोई भी विषय सरकार के एजेंडे में नहीं है। पांच किलो राशन और दो हजार रुपये की किसान सम्मान निधि देकर सरकार किसानों के सभी जायज अधिकारों को खत्म करना चाहती है, लेकिन किसान कांग्रेस किसानों के हक की लड़ाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस संघर्ष करेगी और किसानों को उनका पूरा हक दिलाकर रहेगी।कार्यक्रम के आयोजक एवं किसान कांग्रेस (मध्य जोन) के अध्यक्ष बृज मौर्या ने सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास उन पर जताया है।

मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना में बड़ा फैसला : ग्रामीण बसों के चालकों–परिचालकों का मानदेय बढ़ा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा जनहित में संचालित माननीय मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में चल रही बस सेवाओं को और अधिक सुदृढ़, नियमित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। योजना के तहत बसों के संचालन में लगे चालकों एवं परिचालकों को दिए जाने वाले मानदेय में प्रति किलोमीटर 14 पैसे की वृद्धि की गई है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।इस संबंध में जानकारी देते हुए परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के अंतर्गत अब तक संविदा चालकों एवं परिचालकों को प्रति किलोमीटर 2.18 रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा था। नवीन निर्णय के अनुसार अब यह दर बढ़ाकर 2.32 रुपये प्रति किलोमीटर कर दी गई है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम द्वारा की गई यह वृद्धि बस संचालन से जुड़े चालकों, परिचालकों एवं सेवा प्रदाताओं के लिए आर्थिक संबल का कार्य करेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बसों का संचालन और अधिक नियमित, सुरक्षित एवं सुचारु रूप से किया जा सकेगा।परिवहन मंत्री ने कहा कि इस निर्णय का सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। ग्रामीण अंचलों में आवागमन के लिए निर्भर बड़ी आबादी को बेहतर, निरंतर और भरोसेमंद परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। राज्य सरकार का उद्देश्य केवल बसों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि उनके संचालन को स्थायी, सुरक्षित और यात्रियों के अनुकूल बनाना भी है। इसी दृष्टिकोण के तहत चालकों और परिचालकों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया है।

नेशन फर्स्ट की सोच को साकार करता केंद्रीय बजट : पूर्वांचल से लेकर गांव–गरीब तक विकास को मिलेगी नई गति : एके शर्मा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अपने प्रभार जनपद जौनपुर के निरीक्षण भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट की प्रमुख घोषणाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट 'नेशन फर्स्ट' की भावना को मजबूती देने वाला है और देश के समग्र, संतुलित एवं समावेशी विकास को नई दिशा प्रदान करेगा। यह बजट समाज के प्रत्येक वर्ग—गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग—के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा और अधिक मजबूत हुई है।नगर विकास मंत्री ने कहा कि बजट में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में किए गए प्रावधान ऐतिहासिक हैं। दिल्ली–वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के माध्यम से पूर्वांचल सीधे देश की राजधानी और पूर्वोत्तर भारत से जुड़ेगा। इससे न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि व्यापार, उद्योग और निवेश को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी।उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बजट के प्रावधान पूर्वांचल के लिए वरदान साबित होंगे। मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के निर्णय से सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों की स्थिति में आमजन को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो सकेगा।एके शर्मा ने बताया कि इस बजट में नारी सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। स्वयं सहायता समूहों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने के लिए ठोस पहल की गई है। लखपति दीदी योजना के विस्तार से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कदम सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से दूरगामी प्रभाव डालेंगे।उद्योग और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बजट को ऐतिहासिक बताते हुए मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल्स, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रियायतें दी गई हैं। एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक पार्क के विकास से उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा।नगर विकास मंत्री ने बताया कि म्युनिसिपल बॉन्ड से जुड़े प्रावधानों से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के म्युनिसिपल बॉन्ड पर सौ करोड़ रुपये

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास पर्यावरण शिक्षा, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की आभासी बैठक संपन्न

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के पर्यावरण शिक्षा, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बैठक आभासी माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक का उद्देश्य पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में चल रही गतिविधियों की समीक्षा करना, आगामी कार्ययोजनाओं पर चर्चा करना तथा कार्यकर्ताओं को पर्यावरण संरक्षण हेतु संगठित और प्रेरित करना रहा।

बैठक की अध्यक्षता संजय स्वामी, राष्ट्रीय संयोजक(पर्यावरण शिक्षा) द्वारा की गई। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्र निर्माण से जोड़ते हुए कहा कि प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को जागरूक करना अनिवार्य है।

बैठक में विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉ. चंद्रप्रकाश, राष्ट्रीय सहसंयोजक(पर्यावरण शिक्षा) ने सारगर्भित उद्बोधन दिया। उन्होंने पर्यावरणीय चुनौतियों, जल–जंगल–जमीन के संरक्षण तथा स्थानीय स्तर पर प्रभावी कार्यों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं को निरंतर सक्रिय रहने का आह्वान किया। क्षेत्रीय स्तर पर बैठक के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए डॉ. कीर्ति विक्रम सिंह, क्षेत्रीय संयोजक, पर्यावरण शिक्षा (पूर्वी उत्तर प्रदेश) ने बताया कि न्यास का लक्ष्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आचरण को व्यक्तिगत जीवन में अपनाकर उसे परिवार, कार्यक्षेत्र और समाज तक पहुंचाना है।

बैठक का सफल संचालन रामबाबू, सह संयोजक, पर्यावरण शिक्षा (पूर्वी उत्तर प्रदेश) द्वारा किया गया। बैठक में उपस्थित के. बी. पंत, सहसंयोजक (पर्यावरण शिक्षा - अवध प्रांत) ने पर्यावरणीय गतिविधियों के समन्वय और विस्तार पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे। इस बैठक की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि इं. मून बहादुर ने नेपाल से आभासी रूप से जुड़कर अपने विचार साझा किए। इसके अतिरिक्त काशी प्रांत के संयोजक प्रमोद द्विवेदी , शोध आयाम अवध प्रांत के संयोजक डॉ. अमरपाल, महानगर संयोजक नंदकिशोर शर्मा, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, वाराणसी के निदेशक कृष्णा कृष्णकांत वाजपेई, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह, जिला सहसंयोजक लखनऊ अंकुर अग्रवाल एवं मुकेश कुमार सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही।

बैठक में कुल 45 कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की और सभी ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संकल्प लिए। बैठक में प्रत्येक प्रांत में पर्यावरणीय गतिविधियों के प्रचार-प्रसार हेतु प्रतिमान केंद्र खोलने पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में लूनी नदी के संरक्षण हेतु मार्च माह में एक यात्रा निकालने पर सर्वसम्मति बनी। साथ ही यह भी तय किया गया कि सभी कार्यकर्ता न्यास के पर्यावरण पत्रक प्राप्त करेंगे और उसे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में वितरित करेंगे। अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि वे पहले पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आचरण को स्वयं अपनाएंगे, फिर अपने परिवार को प्रेरित करेंगे और उसके पश्चात अपने कार्यक्षेत्र व समाज में इन मूल्यों का व्यापक प्रसार करेंगे। बैठक सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्ट कार्यदिशा के साथ संपन्न हुई।

छात्रवृत्ति घोटाले का बड़ा खुलासा : मोनाड यूनिवर्सिटी में 53 करोड़ की लूट, छात्रों के विनाश और माफिया के विकास का आरोप

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे ने शुक्रवार को प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश में सामने आए एक बड़े छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ "सबका साथ–सबका विकास" का नारा देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हकीकत यह है कि यहां छात्रों का विनाश हो रहा है और कुछ गिने-चुने कॉलेज व विश्वविद्यालय मालिकों का विकास कराया जा रहा है। हापुड़ स्थित मोनाड विश्वविद्यालय में सामने आया छात्रवृत्ति घोटाला इसी सच्चाई को उजागर करता है।प्रेस वार्ता में वंशराज दुबे ने बताया कि हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी में पिछले 14 वर्षों के दौरान करीब 16,300 छात्रों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर लगभग 53 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति का घोटाला किया गया है। उन्होंने कहा कि यह केवल शुरुआती आंकड़ा है और जांच आगे बढ़ने पर घोटाले की रकम और भी बढ़ सकती है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि ये सभी छात्र सामान्य वर्ग के थे, जिन्हें सत्ता के संरक्षण में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी का दिखाकर वर्षों तक छात्रवृत्ति की रकम हड़पी गई। उन्होंने विश्वविद्यालय के मालिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ सौ से अधिक जालसाजी के मामले दर्ज बताए जाते हैं, इसके बावजूद ऐसे लोग वर्षों से गरीब छात्रों के हक पर डाका डालते रहे और सरकार मूकदर्शक बनी रही।मुख्य प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, जहां छात्र केवल छात्रवृत्ति के सहारे दाखिला लेते हैं। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर कॉलेज प्रशासन छात्रों के बैंक खाते खुलवाता है और उनकी एटीएम कार्ड व पासबुक अपने पास रख लेता है। जैसे ही छात्रवृत्ति की राशि खाते में आती है, उसे निकाल लिया जाता है और छात्रों को इसकी जानकारी तक नहीं दी जाती। उन्होंने इसे सिर्फ घोटाला नहीं, बल्कि दलित, पिछड़े और सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के अधिकारों पर खुली डकैती करार दिया।वंशराज दुबे ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब लगभग सात महीने चली जांच में कई गंभीर तथ्य उजागर हुए। अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2012–13 से 2024–25 तक छात्रवृत्ति की धनराशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है। प्रशासनिक जांच में विश्वविद्यालय को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश तक की गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस मामले में कोई ठोस आपराधिक कार्रवाई नहीं की गई है।उन्होंने सवाल उठाया कि छोटे-छोटे मामलों में ईडी और सीबीआई तुरंत सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन एक विश्वविद्यालय 14 वर्षों तक इतना बड़ा घोटाला करता रहा और उत्तर प्रदेश सरकार चुप्पी साधे रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ "जीरो टॉलरेंस" की बात करते हैं, लेकिन यह घोटाला साबित करता है कि प्रदेश में सौ प्रतिशत करप्शन चल रहा है और डबल इंजन की सरकार पूरी तरह धुआं-धुआं हो चुकी है।

मुख्य प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि इस छात्रवृत्ति घोटाले के तार हापुड़ से होते हुए लखनऊ और दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को शिक्षा, रोजगार और युवाओं के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। मध्य प्रदेश का नर्सिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, उत्तर प्रदेश के कौशांबी का छात्रवृत्ति घोटाला और लगातार हो रहे पेपर लीक इसी मानसिकता का प्रमाण हैं।उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि आज थानों में गरीबों की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, जबकि पुलिस को खुलेआम मनमानी की छूट दी जा रही है। वंशराज दुबे ने स्पष्ट कहा कि गोली मारना पुलिस का काम नहीं है, बल्कि कानून और संविधान के तहत जांच, मुकदमा और सजा की प्रक्रिया होती है।प्रेस वार्ता के अंत में वंशराज दुबे ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच, दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित छात्रों को उनकी पूरी छात्रवृत्ति वापस दिलाने की मांग करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि दोषी चाहे हापुड़ में बैठा हो, लखनऊ में हो या किसी राजनीतिक संरक्षण में हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए।

नगर निगम मुख्यालय निर्माण में देरी पर महापौर सख्त, औचक निरीक्षण में चीफ इंजीनियर को फटकार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। गोमती नगर स्थित नगर निगम वर्कशॉप (आरआर) परिसर में निर्माणाधीन नगर निगम के नवीन मुख्यालय भवन के कार्यों में हो रही लगातार देरी और प्रशासनिक बाधाओं को लेकर शुक्रवार सुबह महापौर सुषमा खर्कवाल ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में सबसे बड़ी बाधा बने पेट्रोल पंप को अब तक स्थानांतरित न किए जाने पर महापौर ने चीफ इंजीनियर आरआर मनोज प्रभात को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान नगर आयुक्त गौरव कुमार भी मौके पर मौजूद रहे।निरीक्षण के समय महापौर ने निर्माण स्थल की वस्तुस्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नगर निगम की वर्कशॉप और उससे जुड़े पेट्रोल पंप को स्थानांतरित करने के निर्देश लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व ही दिए जा चुके थे, इसके बावजूद अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। महापौर ने अधिकारियों से सवाल किया कि जब निर्णय समय रहते ले लिया गया था, तो फिर उसके क्रियान्वयन में इतनी गंभीर लापरवाही कैसे हुई।महापौर ने याद दिलाया कि 16 जुलाई 2024 को नगर विकास मंत्री एके शर्मा द्वारा भूमि पूजन के अवसर पर ही पेट्रोल पंप हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद तत्कालीन नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने भी अपने कार्यकाल के दौरान कई बार इस पंप को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके, संबंधित अधिकारियों द्वारा इन आदेशों की अनदेखी की गई, जिसका सीधा असर नगर निगम के नवीन मुख्यालय भवन के निर्माण कार्य पर पड़ा।उन्होंने बताया कि इस संबंध में नगर निगम के सदन और कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका था। साथ ही चीफ इंजीनियर आरआर को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जब तक नई जगह पर पेट्रोल पंप की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक डीजल और अन्य ईंधन की व्यवस्था किसी वैकल्पिक पंप से सुनिश्चित की जाए।

राष्ट्रीय सुरक्षा और राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता

नीति-निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा और संसदीय विमर्श जैसे गंभीर विषय किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। संसद केवल सत्ता और विपक्ष के टकराव का मंच नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सामूहिक विवेक और जिम्मेदार अभिव्यक्ति का सर्वोच्च स्थल है। ऐसे में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण जैसे संवैधानिक और गरिमामय अवसर पर चर्चा चल रही हो, तब किसी भी नेता से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वह शब्दों, संदर्भों और समय-तीनों के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरते। हालिया घटनाक्रम में लोकसभा में प्रतिनक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के कुछ अंशों का हवाला देकर चीनी सेना की कथित घुसपैठ को लेकर जो बयान दिया गया, उसने इसी अपेक्षा पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए। सरकार का आरोप रहा कि इस बयान ने लोकसभा को गुमराह करने का प्रयास किया, जबकि विपक्ष ने इसे सच दबाने की कोशिश बताकर पलटवार किया। परिणाम यह हुआ कि संसद की कार्यवाही बाधित हुई, तीखी बहस ने पूरे दिन का सत्र स्थगित करा दिया और राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र मूल मुद्दों से हटकर आरोप-प्रत्यारोप बन गया।

यह प्रश्न केवल एक वक्तव्य का नहीं, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय हित की समझ का है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर सार्वजनिक वक्तव्यों में संवेदनशीलता अनिवार्य होती है। सीमाओं से जुड़े तथ्य, सैन्य तैनाती, रणनीतिक आकलन-ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर आधे-अधूरे संदर्भ या चयनित उद्धरण अनावश्यक भ्रम पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे संसदीय नियमों के उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ बताया। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देने के बावजूद यदि किसी नेता का अपने वक्तव्य पर अड़े रहना कार्यवाही को ठप कर दे, तो सवाल उठता है कि क्या उद्देश्य सच सामने लाना था या राजनीतिक लाभ साधना। विपक्ष का दायित्व सत्ता से सवाल करना है, यह लोकतंत्र का प्राण है। किंतु सवालों की भाषा, मंच और समय-तीनों लोकतांत्रिक मर्यादाओं से बंधे होते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का समय सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर समग्र विमर्श का होता है। उस दौरान सैन्य पुस्तकों के चयनित अंशों को राजनीतिक हथियार बनाना, वह भी बिना समुचित संदर्भ और संस्थागत प्रक्रिया के, स्वाभाविक रूप से विवाद को जन्म देता है। विपक्ष का यह कहना कि सरकार असहज प्रश्नों को दबाना चाहती है, एक परिचित एवं बेतूका राजनीतिक तर्क है; परंतु सरकार का यह कहना कि राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीतिक रंग देना अनुचित है, उतना ही वजनदार प्रतिवाद है। दोनों पक्षों के बीच संतुलन वहीं संभव है, जहां तथ्य, प्रक्रिया और समय का सम्मान हो।

संसद के भीतर अप्रकाशित 'संस्मरण' के जिक्र पर विवाद होना स्वाभाविक है। क्योंकि संसदीय परंपराओं और स्थापित नियमों के अनुसार किसी भी सदस्य द्वारा संसद के पटल पर ऐसी प्रकाशित या अप्रकाशित पुस्तक, लेख या पत्रिका की सामग्री को प्रमाण के रूप में उद्धृत करना स्वीकार्य नहीं है, जिसे सदन के समक्ष औपचारिक रूप से प्रस्तुत (टेबल) न किया गया हो। विशेष रूप से ऐसी पुस्तकों या लेखों के अंश, जिनकी न तो संसदीय सत्यापन प्रक्रिया हुई हो और न ही जिन्हें सदन की अनुमति से अभिलेखित किया गया हो, उन्हें तथ्यात्मक प्रमाण मानना संसदीय मर्यादा के विरुद्ध है। इस दृष्टि से राहुल गांधी द्वारा किसी अप्रकाशित पुस्तक के अंशों को सीधे उद्धृत कर उन्हें नीतिगत या राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत करना न केवल संसदीय नियमों की अवहेलना है, बल्कि इससे सदन की गरिमा और कार्यवाही की विश्वसनीयता भी आहत होती है। राहुल गांधी केवल कांग्रेस के नेता ही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में तो उन्हें भारतीय सेनाओं के नैरेटिव के साथ खड़े होना चाहिए। दुर्भाग्य से वे ऐसा नहीं करते। वे चीन और पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार को तो घेरते हैं, लेकिन यह स्मरण नहीं रखते कि इन दोनों देशों ने भारतीय भूभाग पर तब अतिक्रमण किया, जब कांग्रेस सत्ता में थी। गलवान में चीनी सेना के साथ खूनी टकराव के मामले में तत्कालीन सेनाध्यक्ष की अप्रकाशित पुस्तक के कथित अंश का जैसा उल्लेख राहुल गांधी ने किया, उस पर हंगामा होना ही था। आखिर जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई, उसका उल्लेख राहुल कैसे कर सकते हैं? राहुल गांधी का आरोप कि मोदी सरकार ने चीनी सेना के अतिक्रमणकारी रवैये पर साहस नहीं दिखाया, बेबुनिया एवं भ्रमित करने वाला आरोप है। यह पहली बार नहीं है, जब राहुल गांधी ने यह कहने की कोशिश की हो कि प्रधानमंत्री मोदी चीन का डटकर मुकाबला करने से बचते हैं। वे मोदी सरकार को कमजोर दिखाने के लिए यह भी कहते रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। वे यहां तक कह चुके हैं कि चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की थी।

एक दशक में बनाई पूंजी पीके ने बिहार में गंवा दी

बिहार में नीतीश कुमार की बनाई समता पार्टी, जिसे अब जनता दल यू के नाम से जाना जाता है या उत्तर प्रदेश में कांशीराम की बनाई बहुजन समाज पार्टी इसकी मिसाल हैं।

अजीत द्विवेदी

सबसे पहले तो यह समझना होगा कि प्रशांत किशोर ने बिहार में क्या गंवाया है? वे मानें या नहीं मानें लेकिन एक कुशल चुनाव प्रबंधक के रूप में एक दशक में बनाई गई अपनी पूंजी उन्होंने बिहार में गंवा दी है। उनके दो सौ या चार सौ करोड़ रुपए खर्च हुए वह उनका बड़ा नुकसान नहीं है। उनकी पार्टी अपना पहला चुनाव बुरी तरह से हारी यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जब पार्टियां पहले चुनाव में बहुत खराब करने के बाद धीरे धीरे मजबूत होती गईं और बहुत बड़ी बन गईं।

बिहार में नीतीश कुमार की बनाई समता पार्टी, जिसे अब जनता दल यू के नाम से जाना जाता है या उत्तर प्रदेश में कांशीराम की बनाई बहुजन समाज पार्टी इसकी मिसाल हैं। दोनों पार्टियों की शुरुआत बहुत खराब हुई थी। लेकिन दोनों के नेताओं को पता था कि उनका आइडिया और आइडियोलॉजी दोनों सही हैं। इसलिए दोनों मैदान में डटे रहे और राजनीतिक व चुनावी दोनों सफलता हासिल की। इसलिए प्रशांत किशोर का पहला चुनाव हार जाना उनके राजनीतिक करियर का पूर्णविराम नहीं है।

उनके लिए असली चुनौती यह है कि राजनीतिक प्रबंधक के तौर पर जो पूंजी उन्होंने बिहार में गंवाई है उसे कैसे हासिल करेंगे? अगर वे फिर से अपनी उस पूंजी को, उस साख को वापस हासिल कर लेते हैं और बिहार में डटे रहते हैं तो निश्चित रूप से कामयाब होंगे। इसके लिए वे क्या करेंगे, यह उनको शायद ही कोई समझा सकता है। वे खुद समझदार हैं और राजनीति व चुनाव की बारीकियों को बखूबी जानते हैं। वे देश के राजनीतिक इतिहास से भी परिचित हैं। इसलिए उनको पता है कि बिहार में 1995 के विधानसभा चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन करने के बाद नीतीश कुमार ने कैसी राजनीति की थी।

उनको यह भी पता है कि 1984 में बसपा बनाने वाले कांशीराम ने 1989 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन करने के बाद क्या किया था। 1995 में नीतीश कुमार की पार्टी को 324 में से सिर्फ पांच सीटें मिली थीं। इसी तरह 1989 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा को 425 में सिर्फ 13 सीट मिली थी, जो अगले चुनाव यानी 1991 में घट कर 12 हो गई लेकिन उसके दो साल बाद 1993 के मध्यावधि चुनाव में सपा से तालमेल करके बसपा ने 67 सीटें जीतीं और उसी विधानसभा में 1995 में मायावती पहली बार 137 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनीं।

सो, प्रशांत किशोर के लिए राजनीति का रास्ता साफ है। उनके सामने नीतीश कुमार और कांशीराम दोनों का मॉडल है। नीतीश कुमार की समता पार्टी ने 1995 की हार के बाद भाजपा के साथ तालमेल किया और लालू प्रसाद को सत्ता से हटाने के लिए राजनीति की, जिसमें निर्णायक कामयाबी 2005 के अक्टूबर में मिली। यानी पार्टी बनाने के 10 साल बाद। इसी तरह कांशीराम ने बहुजन की सत्ता स्थापित करने के लिए 1984 में बसपा बना कर राजनीति शुरू की तो 11 साल बाद 1995 के जून में मायावती को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हुए। इसके लिए उनको समाजवादी पार्टी से तालमेल करना पड़ा।

उनका सूत्र वाक्य था पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। तीसरे चुनाव में उनको जीत मिली थी हालांकि वह निर्णायक नहीं थी। निर्णायक जीत मिली 2007 में जब बसपा ने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत हासिल किया। सो, जाहिर है कि राजनीति में निरंतरता और समान या असमान विचार वाले दलों के साथ गठबंधन सबसे महत्वपूर्ण है।

तभी प्रशांत किशोर के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने की खबर को उनकी राजनीति के अगले कदम के तौर पर देखा जा सकता है। ध्यान रहे प्रशांत किशोर ने एक समय कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर देश की सबसे पुरानी पार्टी को उसका गौरव लौटाने की योजना पर काम करना चाहा था। उन्होंने लंबा चौड़ा प्रजेंटेशन कांग्रेस नेतृत्व के सामने रखा था। आधे अधूरे तरीके से कुछ प्रस्तावों को कांग्रेस ने आजमाया भी। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के असुरक्षा भाव और प्रशांत किशोर की अति महत्वाकांक्षा के कारण दोनों की बात नहीं बनी। अब फिर दोनों नजदीक आ रहे हैं तो नए किस्म के गठबंधन की आहट सुनाई दे रही है। ध्यान रहे बिहार में हमेशा एक तीसरी ताकत की गुंजाइश है।

नीतीश कुमार के उदय से पहले बिहार में कांग्रेस के मुकाबले समाजवादी पार्टियों के साथ साथ भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ती थीं। धीरे धीरे बिहार की राजनीति दो ध्रुवीय हो गई। प्रशांत किशोर और कांग्रेस अगर तीसरी ताकत बनने की राजनीति करते हैं तो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य दिलचस्प होगा। ध्यान रहे अगले कुछ महीनों या बरसों में बिहार की राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन होगा। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के राजनीतिक परिदृश्य से विदा होने के बाद बिहार की राजनीति वैसी ही नहीं रह जाएगी, जैसी पिछले 35 साल से है। उस समय कांग्रेस और प्रशांत किशोर दोनों के लिए बड़ा अवसर बनेगा।

लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर को चुनाव प्रबंधक और राजनीतिक गुरू के तौर पर अपनी खोई हुई साख को वापस हासिल करना होगा। इस साल होने वाला पांच राज्यों का चुनाव उनके लिए परफेक्ट मौका है। उनकी पुरानी कंपनी आईपैक का करार अब भी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ है। हालांकि आईपैक के साथ अब उनका जुड़ाव नहीं है। लेकिन उन्होंने तमिलनाडु में फिल्म स्टार विजय की पार्टी टीवीके से करार किया है और उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। गौरतलब है कि 2021 में ममता बनर्जी की जीत ने प्रशांत किशोर को सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाया था। उन्होंने दावा किया था कि भाजपा एक सौ सीट तक नहीं पहुंचेगी और भाजपा सचमुच 77 सीट पर रह गई। अब उनके लिए यह मौका तमिलनाडु में बन सकता है। अगर तमिलनाडु में त्रिशंकु विधानसभा बनती है और विजय की ऐसी हैसियत होती है कि उनके बगैर सरकार न बने तो वह भी पीके के लिए बूस्टर डोज साबित हो सकता है।

टीवीके और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चा होना भी प्रशांत किशोर की राजनीति का असर हो सकता है। तमिलनाडु में प्रशांत किशोर अपने को किस तरह से लगाते हैं, क्या मैसेज बनवाते हैं और चुनाव के बाद किस हैसियत में उभरते हैं इससे बिहार की राजनीति में उनकी और उनकी पार्टी की किस्मत बहुत कुछ निर्भर करेगी। कांग्रेस भी अगर उनको आगे मौका देती है तो उसका भी फैसला तमिलनाडु के चुनाव नतीजों से होगा। जो हो उनके लिए अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। इस बीच वे और उनका संगठन फिर से बिहार में सक्रिय हो गए हैं। सोशल मीडिया में पिछले दो महीने में उनकी उपस्थिति बहुत कम हो गई थी लेकिन एक बार फिर उनकी सोशल मीडिया टीम सक्रिय हो गई है।

टिप्पणी

ट्रंप से किसी रहम की उम्मीद नहीं

जब पूछा गया कि क्या उनकी वैश्विक शक्ति की कोई सीमा है, तो डॉनल्ड ट्रंप ने कहा- 'हां, एक चीज है- मेरी अपनी नैतिकता। मेरा अपना दिमाग। यही एक चीज है, जो मुझे रोक सकता है।' जो बातें डॉनल्ड ट्रंप पर बतौर इल्जाम कही जाती थीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब खुद उसकी पुष्टि कर दी है। दो-टूक कहा है कि वे किसी अंतरराष्ट्रीय कानून से बंधे हुए नहीं हैं।

उन्होंने सैनिक, आर्थिक या राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करने के मामलों में अपनी पूरी 'स्वतंत्रता' का एलान किया। कहा कि अपने मकसद को हासिल करने की राह में आने वाली किसी अंतरराष्ट्रीय संधि, कानून, समझौते आदि वे नहीं मानते। जब पूछा गया कि क्या उनकी वैश्विक शक्ति की कोई सीमा है, तो उन्होंने कहा- 'हां, एक चीज है- मेरी अपनी नैतिकता। मेरा अपना दिमाग। यही एक चीज है, जो मुझे रोक सकता है।' राजतंत्र के दौर में समझा जाता था कि राजा की सोच या वह जो कहता है, वही कानून है। ताजा टिप्पणियों से ट्रंप ने उस दौर की मान्यता के अनुरूप खुद को विश्व सम्राट के रूप में पेश किया है। इन बातों की रोशनी में वेनेजुएला में उनके प्रशासन ने क्या किया या ग्रीनलैंड में क्या करने का इरादा रखता है, उसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुई नियम आधारित एवं उदार विश्व व्यवस्था के तर्कों से समझने की कोशिश व्यर्थ हो जाती है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि उस समझ के आधार पर होने वाली आलोचनाओं का उनकी निगाह में कोई महत्त्व नहीं है।

वे दुनिया को नए युग में ले गए हैं, जो शक्ति के सिद्धांत के प्रेरित है। ट्रंप के आचरण में यह बात पहले से ही साफ नजर आती रही है, मगर अब उन्होंने इनको सैद्धांतिक जामा भी पहना दिया है। संदेश यह है कि ट्रंप सिर्फ ताकत का सम्मान करना जानते हैं। संभवतः इसीलिए शी जिनपिंग या व्लादीमीर पुतिन का उल्लेख करते हुए वे उतना अपमानजनक लहजा नजरिया नहीं दिखाते, जैसा इजहार दूसरे नेताओं- जिनमें यूरोपीय नेता भी शामिल हैं- के प्रति करते हैं। भारत जैसे देशों को इसका अर्थ समझना चाहिए। उन्हें ट्रंप से किसी रहम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ट्रंप के दौर में अपने हित की रक्षा कैसे की जाए, यह यक्ष प्रश्न उनके सामने खड़ा है।

ब्लॉग

सत्ता की निष्कंटक राह बरास्ते सुनेत्रा की ताजपोशी

उमेश चतुर्वेदी

राजनीति जज्बात से नहीं, हालात के हिसाब से चलती है। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण इसका उदाहरण है। सुनेत्रा के आंसू अभी सूखे भी नहीं, पति अजित पवार के निधन के शोक से उबरना तो दूर की बात है। फिर भी उन्होंने सियासी तकाजे को ही प्राथमिकता दी और महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। पारिवारिक वज्रपात के बीच सिंहासन पर बैठने को लेकर उनकी आलोचना स्वाभाविक है, क्योंकि समाज के सोचने का अपना ढंग है। सियासी हस्तियों से भी उसे सामाजिक परंपराओं और पारिवारिक संस्कारों को अपनाने की उम्मीद रहती है। सुनेत्रा सामाजिक सवालों से बच नहीं सकतीं। लेकिन सवाल यह है कि सुनेत्रा की ताजपोशी से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर क्या वजह रही कि सुनेत्रा ने आनन-फानन में शपथ ले ली। महाराष्ट्र के राजभवन में जनवरी महीने के आखिरी दिन जो राजनीतिक इतिहास रचा गया, उसकी कहानी किसने लिखी थी।

महाराष्ट्र में भले ही शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली हो, लेकिन राज्य की राजनीति के सबसे मंजे हुए खिलाड़ी शरद पवार हैं। यह बात छुपी हुई नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़ों के बीच सुलह और एकीकरण की बात चल रही थी। शरद पवार तो खुलकर स्वीकार भी कर चुके हैं कि उनकी ओर से जयंत पाटिल, अजित पवार से बात कर रहे थे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 12 फरवरी को दोनो पार्टियों के विलय पर अजित और शरद में सहमति हो चुकी थी। लेकिन अजित के न रहने के बाद समीकरण बदल गए। अजित के साथ गए अहम नेताओं प्रफुल्ल पटेल, आर आर पाटिल और सुनील तटकरे जैसे नेताओं की आशंकाएं बढ़ गईं। उन्हें डर था कि अगर विलय हुआ तो शरद पवार की पार्टी पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। इसके चलते सुप्रिया सुले की पार्टी पर पकड़ बढ़ जाएगी। सुप्रिया के नियंत्रण में इन नेताओं का काम करना असहज होता। प्रफुल्ल कभी शरद पवार के बेहद नजदीकी होते थे। अजित के साथ जाकर एक तरह से उन्होंने शरद पवार के साथ दगाबाजी ही की है। उन्हें ज्यादा आशंका थी कि विलय के बाद पार्टी पर पकड़ होने के चलते शरद के बहाने सुप्रिया का चाबुक उन पर चल सकता है। लेकिन अगर पार्टी अलग रहती है और सुनेत्रा के हाथ कमान रहती है तो इन नेताओं की सियासी सेहत बनी और बची रह सकती है। यही वजह है कि अजित के निधन के चलते हुए आधिकारिक शोक की मियाद खत्म होते ही प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे नेता सक्रिय हो गए। विधायक दल की बैठक बुलाई गई और सुनेत्रा को तत्काल उसका नेता चुनकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार कर लिया गया। शरद पवार भले ही इस सियासी पटकथा का लेखक सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को मानते हों, लेकिन महाराष्ट्र के सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि असल में यह पटकथा राज्य की बीजेपी ने लिखा है। पटेल और तटकरे जैसे नेताओं ने सिर्फ इसे अमल में लाने में भूमिका निभाई है।

सवाल उठ सकता है कि अगर सुनेत्रा शपथ नहीं लेतीं तो क्या बीजेपी की सियासी सेहत गड़बड़ा सकती थी, क्योंकि राज्य में बीजेपी के 132 और एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना के 57 विधायक हैं। राज्य में बहुमत के लिए महज 145 सीटें चाहिए होती हैं। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी की अगुआई वाली सरकार को कोई खतरा नहीं होने जा रहा था। अजित समेत एनसीपी के 41 विधायक पिछले चुनाव में चुने गए हैं। अजित के न रहने पर यह संख्या 40 रह गई है। लेकिन बीजेपी की चिंता दूसरी है। शरद पवार की राजनीतिक स्थिति भले ही ठीक ना हो, लेकिन जैसे ही दोनों एनसीपी का विलय होता, शरद ताकतवर होकर उभरते। महाराष्ट्र का यह चाणक्य एक बार फिर स्थापित होता और बीजेपी के लिए नई सिरदर्दी खड़ी हो जाती। शरद पवार इतने प्रभावी और सियासी रूप से तिकड़मी हैं कि बीजेपी के लिए संकट बनकर उभर जाते। उनकी प्रभावी सक्रियता के चलते शिवसेना के गुटों को भी एक करने की वे कोशिश कर सकते थे। भले ही यह सोच कल्पना लग रही हो, लेकिन एकबारगी स्वीकार कर लें कि ऐसा होता तो महाराष्ट्र की राजनीति कैसी होती।

महाराष्ट्र में जिला परिषदों के चुनाव हो रहे हैं। पहले विधानसभा और बाद में स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की अगुआई वाली महाविकास अघाड़ी को सफलता नहीं मिली। अजित पवार के न रहने के चलते कांग्रेस को सक्रिय होना चाहिए था। अजित की अगुआई वाले जिला परिषद उम्मीदवार उनके न रहने की वजह से थोड़े आशंकित और निराश भी हैं। इस निराशा को कांग्रेस भुना सकती थी। वह एनसीपी के उम्मीदवारों पर डोरे डाल सकती थी और अपने उम्मीदवारों को नए जोश से भर सकती थी। अजित बेशक सत्ता में थे, लेकिन उन्हें विपक्षी खेमे के लिए अब भी हसरतभरी निगाह से ताकतवर नेता के रूप में देखा जा रहा था। अजित के न रहने के बाद विपक्षी नेतृत्व के लिए आसमान खुल गया है। शरद पवार की उम्र हो गई है। शरद के बाहर जाने के बाद से ही कांग्रेस राज्य में कमजोर हुई है। सुप्रिया सुले का नेतृत्व ऐसा नहीं है कि वह राज्यव्यापी प्रभाव हासिल कर पाए। यह माहौल कांग्रेस के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। ऐसे माहौल में कांग्रेस को अपने ताकतवर नेतृत्व को स्थानीय स्तर पर आगे लाना चाहिए था। लेकिन वह ऐसा करती नहीं दिख रही। 2014 के बाद से उसने जिस नैरेटिव युद्ध की शैली को अपनाया है, राष्ट्रीय स्तर पर उसी युद्ध प्रक्रिया को जारी रखे हुए है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास फुर्सत नहीं है कि वह महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य की राजनीति के बारे में स्थानीय जरूरतों के लिहाज से सोचे और स्थानीय समुदायों के लिए उन्हीं के बीच से प्रभावी नेतृत्व उभारे।

रणनीतिक लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी सभी दलों पर एक बार फिर बीस पड़ती नजर आ रही है। उसने सुनेत्रा को अपने खेमे में लाकर एक तीर से दो निशाने साध लिए हैं। उसने एनसीपी की ओर निश्चिंतता हासिल कर ली है, शरद पवार को एक बार फिर किनारे रखने में सफल हुई है और अपने लिए खतरा बनने की शरद की संभावनाओं को एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई देश की आर्थिक राजधानी भी है। इसी वजह से केंद्रीय सत्ता के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली महाराष्ट्र की सत्ता मानी जाती है। माना जाता है कि कारपोरेट और औद्योगिक जगत पर सबसे ज्यादा पकड़ महाराष्ट्र के सिंहासन की होती है। मौजूदा राजनीति में आर्थिकी सबसे ज्यादा प्रभावी है। महाराष्ट्र की सत्ता पर पकड़ देश की आर्थिक ताकतों की नब्ज पर पकड़ बनाती है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी अपनी इस पकड़ को कमजोर होते नहीं देखना चाहती। इसलिए उसने सुनेत्रा को साधने में देर नहीं लगाई। इसके लिए एनसीपी के ही नेताओं को अपना औजार बनाया और सफल रही। वैसे भी शरद पवार उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जहां से उनके लिए गुंजाइश कम है। उनके पास सक्रिय रहने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। बेशक वे अब भी कमजोर हों, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे नहीं, शरद पवार ही हैं। सुनेत्रा को अपने खेमें में लाकर बीजेपी ने शरद की इस बची-खुची चुनौती भी खत्म करने में कामयाब रही है। सुनेत्रा के साथ से एकनाथ शिंदे के लिए महायुति से बाहर निकलने की सोचना या बीजेपी पर दबाव बढ़ाने का मौका खत्म हो जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति शिंदे के साथ के चलते सुनेत्रा की भी रहेगी। बीजेपी सुनेत्रा के जरिए शिंदे को संतुलित करेगी तो शिंदे के जरिए सुनेत्रा को काबू में रखेगी।

मंत्री स्वतंत्र देव को बंधक बनाने वाले बीजेपी विधायक बृजभूषण की बढ़ी मुश्किलें, पार्टी ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

आर्यावर्त संवाददाता

महोबा। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कथित तौर पर बंधक बनाने के मामले में बीजेपी विधायक बृजभूषण उर्फ़ गुड्डू राजपूत को बड़ा झटका लगा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जिससे पार्टी की छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं।

महोबा की चरखारी विधानसभा सीट से विधायक बृजभूषण राजपूत और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच 30 जनवरी को टकराव देखने को मिला था। इस दौरान बीच सड़क पर ही मंत्री और विधायक आमने-सामने आ गए थे।

विधायक ने क्या लगाया था आरोप

विधायक ने आरोप लगाया कि पाइपलाइन डालने के नाम पर सड़कों को खोद दिया गया, लेकिन बाद में उनकी मरम्मत नहीं कराई गई। इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर विधायक और ग्राम प्रधान मंत्री से बातचीत करना चाहते थे।

विधायक और उनके समर्थकों ने मंत्री को बीच सड़क पर रोक लिया था। इसके बाद मामला तनावपूर्ण हो गया था। कुछ देर के लिए वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को हालात सुधारने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि उस समय मामला शांत हो गया था। लेकिन, विधायक ने बाद में लखनऊ जाने की बात भी कही थी। इसी के बाद उनको नोटिस जारी किया गया है।

अब 7 दिन में देना होगा जवाब

यूपी के जल शक्ति कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाने वाले MLA बृजभूषण उर्फ़ गुड्डू राजपूत को नोटिस जारी किया गया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से यह नोटिस गुड्डू राजपूत को जारी किया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि बीजेपी विधायक इसको लेकर क्या सफाई पेश करते हैं।

यूजीसी के समर्थन में सड़क पर उतरे प्रतियोगी छात्र

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। यूजीसी एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर कई छात्र संगठनों ने जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या प्रतियोगी छात्र और इलाहाबाद विवि के छात्रों ने हिस्सा लिया। हाथ में नारे और स्लोगन लिखी तख्तियां और बाबा साहब अंबेडकर का चित्र लेकर सरकार से मांग की गई कि यूजीसी एक्ट को तत्काल लागू किया जाए ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को उनका हक मिल सके।

यूजीसी के नए नियम लागू करने की मांग को लेकर अब प्रयागराज में भी प्रदर्शन हुआ। शुक्रवार को समर्थन में छात्र सड़कों पर उतरे। "ब्राह्मणवाद का नाश हो", "वोट हमारा, राज तुम्हारा₹ जैसे नारे लिखे प्लेकार्ड लहराते हुए छात्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

छात्रों के हाथों में डॉ. अंबेडकर और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आत्महत्या करने वाले छात्र रोहित वेमुला की बड़ी-बड़ी तस्वीरें थीं। कुछ छात्र तिरंगा भी लहरा रहे थे। सुबह करीब 11 बजे शहर के बैंक रोड पर सैकड़ों छात्र एकत्र हुए। नारेबाजी करते हुए जैसे-जैसे वे आगे बढ़े, अलग-अलग जगहों से छात्र उनके साथ जुड़ते चले गए। रैली जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंची, तब तक छात्र-छात्राओं की संख्या बहुतायत से अधिक हो चुकी थी। नारेबाजी करते हुए जैसे ही रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, बड़ी संख्या में वकील भी समर्थन में उतर आए और नारे लगाने लगे। उधर, छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती रही।

ज्ञात हो कि 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भेदभाव रोकने से जुड़े यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी थी। कोर्ट का कहना था कि नियमों के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका है। यूजीसी के वर्ष 2012 के नियमों में संशोधन के बाद 13 जनवरी 2026 को नए नियम जारी किए गए थे। छात्रों का एक वर्ग इन नियमों को जरूरी बता रहा है, जबकि दूसरा वर्ग इसका विरोध कर रहा है।

दोस्तों को सौंप दी पत्नी, दो युवकों ने मिलकर किया गैंगरेप... दी चुप रहने की धमकी

आर्यावर्त संवाददाता

अमरोहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नशेड़ी पति ने अपनी ही पत्नी को दो दोस्तों के हवाले कर दिया। इसके बाद दोनों दोस्तों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर घटना के संबंध में किसी को भी न बताने की धमकी देते हुए चुप रहने को कहा।

घटना अमरोहा जनपद के थाना नौगांवा क्षेत्र की है, जहां के रहने वाले एक नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी को अपने दो दोस्तों के साथ जाकर किसी व्यक्ति से पैसे लाने के लिए कहा। उसने पत्नी से कहा कि वह उसके दोस्तों के साथ जाकर उसके पैसे ले आए।

जब पत्नी ने दोस्तों के साथ जाने से मना किया तो पति ने कहा कि वह बेफिक्र रहे, वह भी पीछे से बाइक लेकर आ रहा है। इसके बाद उसने पत्नी को दोस्तों के साथ भेज दिया। इसी दौरान पति के दोस्तों ने महिला को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर पहले बंधक बनाया।

इसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। जब पीड़ित महिला ने अपने पति को आपबीती बताई तो पति ने दोस्तों के खिलाफ पुलिस में कार्रवाई कराने के बजाय पत्नी पर ही चुप रहने का दबाव बनाया और धमकी दी कि वह किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करेगी।

लेकिन जब पीड़ित महिला का एक सप्ताह बाद सब्र का बांध टूट गया तो उसने पूरी घटना की जानकारी अपने भाई को दी। इसके बाद महिला का भाई उसे थाने लेकर पहुंचा और घटना के संबंध में पुलिस को तहरीर दी।

तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने पति और उसके दो दोस्तों सहित तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पति द्वारा पत्नी के साथ कराई गई इस तरह की घटना ने पति-पत्नी के रिश्ते के विश्वास को भी झकझोर कर रख दिया है।

शादी समारोह में सूट-बूट पहन कर आए चोर, 50 लाख के गहने लेकर हुए फरार, चोरी सीसीटीवी में कैद

आर्यावर्त संवाददाता

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से शूट-बूट वाले चोरों ने शादी के कार्यक्रम से लाखों का माल साफ कर दिया। शादी के माहौल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लड़की के पिता को पता चला कि उनका ज्वेलरी से भरा बैग गायब हो गया है। आसपास काफी ढूंढने पर बैग नहीं मिला तो बैंक्वेट हॉल में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। तब जाकर पता चला कि ज्वेलरी से भरे बैग पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। मामला संज्ञान में आने के बाद शादी की खुशियों की रौनक फीकी पड़ गई।

चोरों ने उठाया मौके का फायदा

जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा की इकोटेक थर्ड कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चोगानपुर गांव स्थित गोल्डन ड्रीम फार्म हाउस में एक

डॉक्टर की बेटी की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। सभी मेहमान शादी समारोह में व्यस्त थे। एक तरफ शहनाई बज रही थी तो दूसरी तरफ मेहमान खाने का लुत्फ उठा रहे थे।

इसी बीच दो चोर सूट-बूट पहनकर आए और उन्होंने सीधे उस बैग को निशाना बनाया, जिसमें करीब 50 लाख रुपये की ज्वेलरी रखी थी। चोरों ने बड़ी आसानी से वह बैग उठाया और वहां से कुछ ही सेकंड में रफूचक्कर हो गए।

रस्में खत्म होने के बाद हुई जानकारी

जानकारी के अनुसार फार्म हाउस में शादी समारोह धूमधाम से चल रहा था। परिवार के सभी सदस्य और मेहमान विवाह की रस्मों में व्यस्त थे। इसी दौरान दो युवक मेहमानों की तरह शादी में शामिल हुए और मौका देखकर ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। इस दौरान किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ, क्योंकि दोनों पूरी तरह से शादी के मेहमानों की तरह तैयार होकर आए थे।

शादी समारोह के बाद जब बेटी की विदाई का समय आया, तब पिता ने ज्वेलरी देने के लिए बैग ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। रिश्तेदारों ने भी बैग को काफी तलाश किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तुरंत फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, तो पता चला कि दो युवक शादी समारोह में शामिल हुए थे और उन्होंने ही बैग चोरी किया। इस घटना के बाद फार्म हाउस में हड़कंप मच गया।

पीड़ित ने नहीं दी कोई शिकायत

कोतवाली प्रभारी इकोटेक थर्ड ने बताया कि घटना देर रात की है। फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जो संदिग्ध लोग कैमरे में कैद हुए हैं, उनकी पहचान की जा रही है। हालांकि पीड़ित पक्ष की ओर से अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।

फार्म हाउस प्रबंधन की ओर से एक शिकायत मिली है, जिस पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित परिवार से भी बात की गई है और उनसे शिकायत लेने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।

'आ नहीं सकते तो...', दूल्हे ने शादी का ऐसा कार्ड छपवाया, सोशल मीडिया पर हो गया वायरल

आर्यावर्त संवाददाता

बागपत. उत्तर प्रदेश के बागपत में शादी का एक अनोखा कार्ड वायरल हुआ है। दरअसल, यहां एक परिवार में शादी के दो प्रोग्राम हैं। यानि बेटी की भी शादी है और बेटे की भी। बेटे आकाश ने शादी का ऐसा कार्ड छपवाया है, जिसकी चर्चा हर कहीं हो रही है। शादी में एक QR कोड छपवाया गया है। इसके पीछे का कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

दूल्हा बनने जा रहे आकाश ने कहा- शादी में दूर-दूर से कई रिश्तेदार आते हैं। उन्हें पहले कार्ड देने के लिए भी जाना पड़ता है। मगर कई बार कार्ड देने जाने के चक्कर में और शादी समारोह में आने के वक्त सड़क हादसे हो जाते हैं। बस इन्ही को देखते हुए QR कोर्ड वाला कार्ड छपवाया गया है। यानि अगर रिश्तेदार शादी में किसी कारणवश नहीं भी आ पाएं तो QR कोड को स्कैन करके शगुन भेज सकते हैं। दूल्हे का ये भी मकसद है कि अनावश्यक खर्च और समय की भी बचत भी इससे हो सके।

7 और 8 फरवरी को हैं दोनों शादियां

दोघट कस्बा निवासी आकाश बाल्मीकि ने अपनी बहन और अपनी शादी के कार्ड पर QR कोड छपवाया है। आकाश ने बताया कि 7 फरवरी को उसकी बहन की शादी है और 8 फरवरी को उसकी खुद की शादी संपन्न होगी। दोनों शादियों के कार्ड पर छपे QR कोड के माध्यम से अब कन्यादान और दुल्हन की मुंह दिखाई का शगुन ऑनलाइन भेजा जा सकेगा। आकाश का कहना है कि शादी-विवाह के अवसर पर रिश्तेदार और परिचित अक्सर दूर-दराज से समारोह में शामिल होने के लिए यात्रा करते हैं। इस दौरान कई बार सड़क हादसे हो जाते हैं, जिससे खुशियों का माहौल मातम में बदल जाता है। इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने यह कदम उठाया, ताकि दूर रहने वाले रिश्तेदार बिना यात्रा किए सुरक्षित तरीके से अपनी शुभकामनाएं और शगुन भेज सकें।

लोग कर रहे इस पहल की सराहना

उन्होंने बताया कि जिन रिश्तेदारों के लिए आना संभव नहीं है या जो दूरी और व्यस्तता के कारण नहीं आ पाते, वे QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन कन्यादान या मुंह दिखाई का शगुन भेज सकते हैं। इससे न केवल उनकी सुरक्षा बनी रहेगी, बल्कि आने-जाने में होने वाला फजूल खर्च भी बचेगा। आकाश ने अपनी इस पहल के तहत पंजाब, चंडीगढ़, पानीपत समेत अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल कार्ड भेजे हैं, जबकि आसपास के इलाकों में कार्ड स्वयं जाकर वितरित किए हैं।

इस अनोखी सोच की क्षेत्र में काफी सराहना हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहल समय की जरूरत है और इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। तकनीक के सही इस्तेमाल से परंपराओं को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा सकता है। आकाश की यह सोच आने वाले समय में अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है।

भारत में स्वच्छता, जाति और वर्ग में गहरा अंतर्सम्बन्ध : प्रो सक्सेना

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग द्वारा विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। जिसके मुख्य वक्ता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफ़ेसर आशीष सक्सेना थे।

कार्यक्रम का आरंभ महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर आशिमा घोष के द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान करने तथा समाजशास्त्र विभाग की समन्वयक प्रो नंदिनी मुखर्जी के द्वारा मुख्य अतिथि को भेंट स्वरूप पौधा दे कर किया गया। तत्पश्चात महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोसेसर आशिमा घोष ने स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत किया।

इसके पश्चात समाजशास्त्र विभाग की प्रभारी डॉ. शालिनी सिंह ने मुख्य अतिथि का परिचय प्रस्तुत किया। इसी क्रम में प्रोफेसर आशीष सक्सेना ने

₹इश्यू ऑफ कास्ट क्लास और सैनिटेशन इन कंटेंपरेरी इंडिया₹ विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि समकालीन भारत में स्वच्छता, जाति और वर्ग में गहरा अंतर्सम्बन्ध है। जाति व्यवस्था ने पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा को संस्थागत रूप दिया। उनके अनुसार जाति यह निर्धारित करती है कि स्वच्छता कार्य कौन करेगा जबकि वर्ग यह निर्धारित करता है कि स्वच्छता सुविधाओं तक किसकी पहुंच होगी। निकोलस बी. डर्क्स, लुई ड्यूमों, एम एन श्रीनिवासन जैसे समाजशास्त्रियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने समकालीन भारत में जाति वर्ग और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर व्यापक प्रकाश डाला।

इस अवसर पर समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित की गई अंतरमहाविद्यालयी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार एस एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्रा शुमायला हुसैन, द्वितीय पुरस्कार जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्रा राजेश्वरी पांडेय, तृतीय पुरस्कार एस एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्रा वर्षा मालवीय तथा सांत्वना पुरस्कार आर्य कन्या डिग्री कॉलेज की छात्रा शिवानी को प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉ. ऐश्वर्य सिंह ने किया।

कार्यक्रम का संचालन बी. ए. द्वितीय वर्ष की छात्राओं अंतरा त्रिपाठी और सुहानी ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की शिक्षिकाएं डॉ नम्रता डेब, डॉ प्रमा द्विवेदी, डॉ अंकिता चतुर्वेदी, डॉ शारदा, डॉ. निर्मला गुप्ता उपस्थित रही।

प्रतापगढ़ में एफआईआर होने पर भड़के अधिवक्ता

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। सिविल लाइंस में अधिवक्ताओं के साथ मारपीट करने वाले टायर कारोबारी को गिरफ्तार करने और प्रतापगढ़ के महेशगंज थाने में अधिवक्ताओं के खिलाफ केस दर्ज करने के विरोध में साथी अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) कार्यालय का घेराव कर सड़क जाम कर दिया। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। अधिवक्ताओं ने आईजी पर अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता का आरोप लगाया। अधिववक्ता पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं।

महेशगंज थाने में तैनात दरोगा शिवा प्रजापति के अनुसार दो फरवरी की रात वह गश्त पर निकले थे। रात करीब 11.15 बजे हीरागंज बाजार स्थित एक गेस्ट हाउस के करीब के द्वारपूजा के लिए जा रही बरात व महेशगंज थाना क्षेत्र के अन्नावा निवासी ट्रक चालक संजीव मौर्य के बीच मारपीट की सूचना मिली। बरात में शामिल कुछ लोग खुद को अधिवक्ता बताने लगे। हंगामा बढ़ने पर चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मियों को बुलाया गया।

दरोगा की तहरीर पर प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के राजरूपपुर निवासी उमापति त्रिपाठी, झलवा के हिमांशू अग्रहरि, वीरेंद्र सिंह, राजा शुक्ला, अंशुमान, अवनीश शुक्ला व कालिंदीपुर निवासी ओसामा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। रात में हिरासत में लिए गए लोगों के पक्ष में कई अधिवक्ता थाने पहुंचे। इस बीच थानाध्यक्ष राधेश्याम व अधिवक्ताओं के बीच तकरार हुई। सीओ सदर करिश्मा गुप्ता के आदेश पर घटनास्थल पर दरोगा से विवाद करने व ट्रक चालक से मारपीट करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

डायरिया से डर नहीं' कार्यक्रम के तहत पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित

सदफ सलमान प्रथम, माहे उरूज दूसरे व जारा तीसरे स्थान पर रहीं

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को प्रताप सिंह हिंदू गर्ल्स इंटर कॉलेज में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गयी। डायरिया के प्रति जागरूकता के लिए इस मौके पर नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 58 छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें कक्षा-11 की सदफ सलमान पहले, कक्षा-11 की ही माहे उरूज दूसरे और कक्षा -9 की जारा तीसरे स्थान पर रहीं। कक्षा-9 की इमरा को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर छात्राओं एवं अध्यापकों की हीमोग्लोबिन की जांच भी की गई।

प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राओं को डायरिया रोकथाम और प्रबन्धन के बारे में विस्तार से बताया गया। नुक्कड़ नाटक और पोस्टर के जरिए डायरिया से बचाव के जरूरी सन्देश दिए गए कि टीकाकरण सारणी के अनुसार सारे टीके लगवाएं और रोटावायरस, विटामिन ए को लेना न भूलें। भोजन को ढककर रखें ताकि मक्खियाँ उस पर न बैठें। जिंक की खुराक को दस्त ठीक होने के बाद भी 14 दिनों तक जारी रखें। पीने के पानी को साफ़ रखें और पीने के पानी को निकालने के लिए डंडीदार लोटे का प्रयोग करें । छह माह से छोटे बच्चों को दस्त होने पर भी स्तनपान जारी रखें। डायरिया के दौरान ओआरएस से शरीर में पानी की कमी को रोकें।

इस मौके पर प्रधानाचार्य सीमा शर्मा, विद्यालय के समस्त शिक्षक के साथ स्वास्थ्य विभाग से तारिक अंसारी, हेमा एवं लैब टेक्नीशियन संदीप और पीएसआई इंडिया से कोमल घई, मोहम्मद रिजवान, ममता सैनी आदि उपस्थित रहे।

क्या होती है पांडा पेरेंटिग, ये आपके बच्चे के लिए कैसे है सही?

बच्चों की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं है। बच्चें ज्यादा सेंसटिव होते हैं ऐसे में उनका काफी ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो सब अपने तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। लेकिन इस वक्त एक अनोखा और दिलचस्प पेरेंटिंग स्टाइल काफी ट्रेंड में है। इसे 'पांडा पेरेंटिंग' कहा जाता है। चलिए जानते हैं की पांडा पेरेंटिग क्या है?

बच्चों की परवरिश एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा खुशहाल, आत्मनिर्भर और सफल बने। लेकिन बच्चों को सही डायरेक्शन में गाइड करना और उनके साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। पेरेंटिंग के कई तरीके होते हैं, जिनमें से हर एक के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। हाल ही में, एक अनोखे और दिलचस्प पेरेंटिंग स्टाइल ने सबका ध्यान आकर्षित किया है जिसे "पांडा पेरेंटिंग" कहा जाता है।

आपने पांडा नाम सुनते ही प्यारे और शांत जानवर की छवि अपने मन में बना ली होगी। दरअसल, पांडा पेरेंटिंग का आइडिया भी इसी से इंस्पायर्ड है। ये पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों को प्यार और सहजता से पालने पर जोर देती है, बिना उन पर बेवजह का दबाव डाले। इसमें माता-पिता अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिश्ता बनाते हैं और उन्हें अपने एक्सपीरियंस से सीखने का मौका देते हैं। आज इस आर्टिकल में हम आपको पांडा पेरेंटिग के फायदे बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या ये आपको बच्चों के लिए सही है?

पांडा पेरेंटिंग क्या है?

पांडा पेरेंटिंग एक ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल है, जिसमें माता-पिता बच्चों को खुद की गलतियों से सीखने और जीवन के अनुभवों को महसूस करने का मौका देते हैं। इसमें बच्चों पर सख्ती या दबाव नहीं डाला जाता, बल्कि उन्हें ये समझाया जाता है कि वे खुद अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं।

इस पेरेंटिंग स्टाइल का नाम पांडा से इसलिए लिया गया है, क्योंकि पांडा जानवर अपने बच्चों के साथ बहुत ही पेशेंस बिहेवियर रखते हैं । पांडा पेरेंटिंग का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाना है, लेकिन साथ ही उन्हें माता-पिता के प्यार और सहारे का एहसास भी कराना है।

पांडा पेरेंटिंग के मुख्य सिद्धांत

सपोर्टिव लेकिन सख्त नहीं : माता-पिता बच्चों को उनके फैसले खुद लेने देते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर गाइड भी करते हैं।

गलतियों से सीखने का मौका : बच्चे अगर गलतियां करते हैं, तो उन्हें डांटने या सजा देने के बजाय ये समझाया जाता है कि इन गलतियों से वे क्या सीख सकते हैं।

इमोशनल कनेक्शन : माता-पिता बच्चों की इमोशन्स को समझते हैं और उनके साथ खुलकर बात करते हैं।

खुद की पहचान बनाने में मदद : बच्चे को उसकी हॉबी और पसंद के आधार पर खुद को खोजने और अपनी पहचान बनाने का मौका दिया जाता है।

पांडा पेरेंटिंग के फायदे

बच्चों में आत्मनिर्भरता बढ़ती है: बच्चे अपने फैसले खुद लेना सीखते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं।

खुद पर भरोसा करना सीखते हैं: पांडा पेरेंटिंग बच्चों को ये एहसास दिलाती है कि उनके इमोशन्स और थोट्स इम्पोर्टेंट हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है।

इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं: माता-पिता का सपोर्ट और प्यार बच्चों को इमोशनली तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाता है।

प्रोब्लम सॉल्विंग एबिलिटी: बच्चे अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढना सीखते हैं, जिससे उनमें जिम्मेदारी और समझदारी बढ़ती है।

पेरेंट्स और बच्चों के बीच बेहतर रिश्ता: पांडा पेरेंटिंग में बच्चे और माता-पिता के बीच एक मजबूत और फ्रेंडली रिश्ता बनता है।

क्या पांडा पेरेंटिंग हर बच्चे के लिए सही है?

पांडा पेरेंटिंग हर बच्चे के लिए सूटेबल हो सकती है, लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके बच्चे का बिहेवियर कैसा है। अगर आपका बच्चा ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये पेरेंटिंग स्टाइल उसे बेहतर तरीके से संभाल सकता है। अगर बच्चा जिद्दी है, तो इस पेरेंटिंग स्टाइल में पेशेंस और समय देना होगा।

कैसे अपनाएं पांडा पेरेंटिंग?

बच्चों को हर समय कंट्रोल करने के बजाय उन्हें अपने एक्सपीरियंस से सीखने का मौका दें। गलतियों पर डांटने की बजाय समझाएं और पॉजिटिव तरीके से उन्हें सुधारने का तरीका सिखाएं। बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएं और उनके इमोशन्स को समझने की कोशिश करें। साथ ही उन्हें नए एक्सपीरियंस के लिए इनकरेज करें और उनकी हॉबिस की रिसपेक्ट करें। इसके अलावा एक हेल्पफुल और फ्रेंडली माहौल बनाएं, ताकि वे आपसे खुलकर बात कर सकें।

क्या पौधों पर आधारित डाइट से आती है कमजोरी? जानें इस मिथक की सच्चाई

पौधों पर आधारित डाइट को लेकर कई तरह के मिथक प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह है कि यह डाइट कमजोरी का कारण बनती है।

पौधों पर आधारित डाइट में फल, सब्जियां, अनाज और दालें शामिल होती हैं, जो पोषण के अच्छे स्रोत होते हैं। इस लेख में हम इस मिथक की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे।

आइए जानते हैं कि कैसे यह डाइट आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है और इसके क्या प्रभाव होते हैं।

पौधे आधारित डाइट के जरिए मिलते हैं सभी पोषक तत्व

पौधे आधारित डाइट में विटामिन, खनिज और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं। फल और सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं।

इसके अलावा, अनाज और दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं, जो मांसपेशियों के विकास के लिए अहम होते हैं।

सही संतुलन बनाए रखने से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते रहते हैं, जिससे कमजोरी नहीं आती, बल्कि ऊर्जा बनी रहती है।

क्या इस डाइट में होती है प्रोटीन की कमी?

अक्सर कहा जाता है कि पौधे आधारित डाइट से पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता, लेकिन यह सच नहीं है। दालें, चने और टोफू और टेम्पेह जैसे सोया उत्पाद प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं।

इनका नियमित सेवन करने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है, जिससे मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और कमजोरी महसूस नहीं होती।

सही संयोजन बनाकर खाने से सभी आवश्यक अमीनो एसिड भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं।

क्या इस डाइट से कम हो जाती है ऊर्जा?

पौधे आधारित डाइट अपनाने वाले लोग अक्सर ऊर्जा कम होने की शिकायत करते हैं, लेकिन इसका कारण गलत खान-पान होता है न कि खुद आहार प्रणाली।

सही समय पर भोजन करना और संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेना ऊर्जा स्तर बनाए रखने में मदद करता है।

ब्राउन राइस या ओट्स जैसे साबुत अनाज खाने से लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती है, जिससे आप दिनभर सक्रिय रह सकते हैं और बिना थकावट महसूस किए काम कर सकते हैं।

इस डाइट का मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है सकारात्मक प्रभाव

शोध बताते रहे हैं कि पौधे आधारित डाइट मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। फल और सब्जियों का सेवन करने से तनाव कम होता है और मूड बेहतर बनता है।

इसके अलावा, इस की डाइट अपनाने से नींद भी अच्छी आती है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, दोनों पर असर डालती है।

जब आप इस तरह की डाइट लेकर अच्छा महसूस करते हैं, तो आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है और आप ज्यादा ऊर्जावान रहते हैं।

खास मौके पर जान्हवी कपूर की तरह दिखना चाहती हैं गॉर्जियस? ऐसे स्टाइल करिए एथनिक ऑउटफिट्स

अगर आपको कोई पार्टी या फंक्शन अटेंड करना है और कोई ड्रेस समझ में नहीं आ रही है तो इस मामले में आप बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर से मदद ले सकती हैं। दरअसल, जान्हवी का फैशन सेंस काफी कमाल है। उनके स्टाइल स्टेटमेंट की हर जगह तारीफ होती है। इसी क्रम में एक्ट्रेस के ऐसे कई एथनिक आउटफिट्स हैं, जिन्हें आप किसी खास मौके के लिए रीक्रिएट कर सकती हैं। जान्हवी कपूर के एथनिक लुक्स को रीक्रिएट करके आप न सिर्फ गॉर्जियस दिखेंगी, बल्कि हर जगह आपके ऑउटफिट की काफी तारीफ भी होगी।

बता दें कि जान्हवी कपूर की गिनती फैशनेबल एक्ट्रेसेस में होती है। ऐसे में उनके ट्रेडिशनल आउटफिट को रीक्रिएट करने का मतलब है कि आप पार्टी में स्टाइलिश दिखेंगी। तो आईये किसी खास मौके पर ग्लैमरस और गॉर्जियस दिखने के लिए एक्ट्रेस के खूबसूरत एथनिक आउटफिट्स पर एक नजर डालते हैं।

पटियाला सूट में कहर ढा रहीं जान्हवी कपूर

अगर आप खास मौके पर पटियाला सूट कैरी करना चाहती हैं तो आप जान्हवी कपूर के इस लुक को रीक्रिएट कर सकती हैं। एक्ट्रेस ने पिंक और येलो पटियाला सूट को बहुत ही ग्रेसफुली स्टाइल किया है। इस सूट के साथ एक्ट्रेस ने येलो टाई एंड डाई दुपट्टे को पेयर किया है, जिसमें पिंक और गोल्डन कलर का बॉर्डर है।

शानदार है जान्हवी कपूर का मरमेड लुक

किसी खास मौके पर ग्लैमरस दिखने के लिए आप जान्हवी कपूर के इस मरमेड लुक से आइडियाज ले सकती हैं। एक्ट्रेस ने यहां मरमेड-कट लॉन्ग स्कर्ट को गोल्डन डीप-नेक ब्लाउज के साथ पेयर किया है, जिसमें वो स्टनिंग लग रही हैं। जान्हवी ने अपने लुक को गोल्डन कलर के क्लच और हैवी इयररिंग्स के साथ कम्पलीट किया है। जान्हवी कपूर इस लुक में एलिगेंट लग रही हैं।

लहंगा-चोली लुक को रीक्रिएट करिए

अगर आप साड़ी नहीं पहनना चाहती हैं तो एक्ट्रेस से लहंगा-चोली स्टाइल करने के बेहतरीन टिप्स ले सकती हैं। डीप नेक वाली चोली और बारीक काम वाले लहंगे में जान्हवी कपूर बेहद खूबसूरत लग रही हैं। एक्ट्रेस ने हैवी ज्वेलरी लुक कैरी किया हुआ है। जान्हवी ने मैचिंग दुपट्टा, मांग टीका, झुमके, चोकर नेकलेस, चूड़ियां और अंगूठियों के साथ अपना लुक पूरा किया है। आप चाहें तो इस लुक के साथ बन हेयरस्टाइल भी बना सकती हैं।

एक्ट्रेस का साड़ी लुक भी किसी से कम नहीं

अगर आप पार्टी में शिमरी साड़ी स्टाइल करने की सोच रही हैं तो जान्हवी कपूर का ये लुक आपके लिए परफेक्ट है। एक्ट्रेस ने यहां पर्पल कलर साड़ी को डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ पेयर किया है। जान्हवी ने अपने लुक को खूबसूरत इयररिंग्स, रिंग और डिसेंट से नेकलेस के साथ कम्पलीट किया है। एक्ट्रेस का सटल मेकअप और ओपन हेयर उनके ओवरऑल लुक को और भी खूबसूरत बनाने का काम कर कर रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों को मिलती है 25 लाख की ग्रेच्युटी, कितना भरना पड़ेगा टैक्स?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी लिमिट बढ़कर 25 लाख रुपये हो चुकी है. हर कोई यह जानना चाहता है कि सरकार ने जो ग्रेच्युटी बढ़ाई है, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं। इस आर्टिकल में जानें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह लिमिट कैसे काम करेगी, और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए क्या नियम हैं।

भारत सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। यह सीमा 1 जनवरी 2024 से लागू हो गई है। इससे पहले यह सीमा 20 लाख रुपये थी। इस इजाफे के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट या मृत्यु के कारण मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम में बढ़ोतरी हो गई है। सरकार ने यह फैसला 'सातवें वेतन आयोग' की सिफारिशों के तहत किया है।

30 मई 2024 को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें नई ग्रेच्युटी लिमिट का ऐलान किया गया था।

ग्रेच्युटी पर टैक्स?

सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी मिलने पर टैक्स की बात करें, तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट या मृत्यु के कारण मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह से इनकम टैक्स फ्री होती है। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स मुक्त रहेगी।

पिछले साल अच्छा नहीं हुआ अप्रैजल? अब इस साल इतनी बढ़ सकती है सैलरी

प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी नियम

प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के नियम अलग हैं। प्राइवेट कर्मचारी चाहे 'पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972' के तहत आते हैं या नहीं आते हैं, तो भी उन्हें 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री मिलती है। इस सीमा के ऊपर की रकम पर टैक्स लागू होता है। इस मामले में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों जैसा नियम नहीं है।

प्राइवेट कर्मचारियों की ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ेगी?

मौजूदा समय में प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेच्युटी लिमिट 20 लाख रुपये तक है। इसे अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। अगर सरकार प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाना चाहती है, तो इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी करना होगा। फिलहाल, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की टैक्स छूट सीमा 20 लाख रुपये तक ही है।

कुल मिलाकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स फ्री मिल रही है, जबकि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए यह सीमा 20 लाख रुपये तक है। अगर प्राइवेट कर्मचारियों को भी यह फायदा देना है, तो इसके लिए अलग से सरकारी आदेश की जरूरत होगी।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अहम प्रगति हुई है। दोनों देश अगले 4-5 दिनों में संयुक्त बयान जारी कर उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। वहीं, व्यापार समझौते के पहले चरण का कानूनी मसौदा मार्च के मध्य तक तैयार होने की संभावना है।

भारत–अमेरिका व्यापार समझौते : सरकार बोली– मार्च तक आएगा कानूनी मसौदा ; 4–5 दिनों में संयुक्त बयान

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दोनों देश अगले 4 से 5 दिनों में संयुक्त बयान (जॉइंट स्टेटमेंट) पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार

सरकार ने बताया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है। उन्होंने बताया कि संयुक्त बयान के बाद इस समझौते को औपचारिक रूप दिया जाएगा और मार्च के मध्य तक फॉर्मल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जॉइंट स्टेटमेंट के जारी होने के बाद ट्रंप सरकार अमेरिकी टैरिफ को 18 फीसदी तक घटाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेगी।

भारत और जीसीसी ने किए टीओआर पर हस्ताक्षर

उद्योग मंत्री ने गुरुवार को भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान कहा कि अमेरिका के साथ बढ़ते कारोबारी जुड़ाव के तहत अमेरिकी विमान, इंजन और अन्य उत्पादों के लिए भारत के ऑर्डर अकेले 100 अरब डॉलर से अधिक हो जाएंगे।

गोयल ने कहा कि भारत और जीसीसी के बीच व्यापारिक रिश्ते 5,000 साल पुराने हैं और यह समझौता वस्तुओं व सेवाओं के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि सरकार विकसित देशों के साथ एफटीए पर सक्रियता से काम कर रही है।

मंत्री के मुताबिक, इस समझौते से एमएसएमई, किसान, मछुआरे, युवा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों को इससे उल्लेखनीय फायदा होने की उम्मीद है।

भारत-अमेरिका हैं एक-दूसरे के पूरक

उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका एक-दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगा। समझौते की प्रक्रिया पर तकनीकी स्पष्टता देते हुए वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ एग्जीक्यूटिव टैरिफ हैं, जबकि भारत के टैरिफ एमएफएन (सबसे पसंदीदा राष्ट्र) श्रेणी में आते हैं। ऐसे में भारत में एमएफएन टैरिफ में कमी कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ही संभव होगी।

गोयल ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की फरवरी 2025 की अमेरिका यात्रा के बाद से दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। 2 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई फोन बातचीत के बाद इस ट्रेड डील की औपचारिक घोषणा हुई थी।

मंत्री ने सदन में यह भी स्पष्ट किया कि करीब एक साल चली वार्ताओं के दौरान दोनों पक्षों ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की। भारत ने खास तौर पर कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों को संरक्षण दिया, जबकि अमेरिका के लिए अहम क्षेत्रों पर भी संतुलन बनाया गया।

यह द्विपक्षीय व्यापार समझौता 2025 में औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया गया था, जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत-अमेरिका व्यापार को 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है।

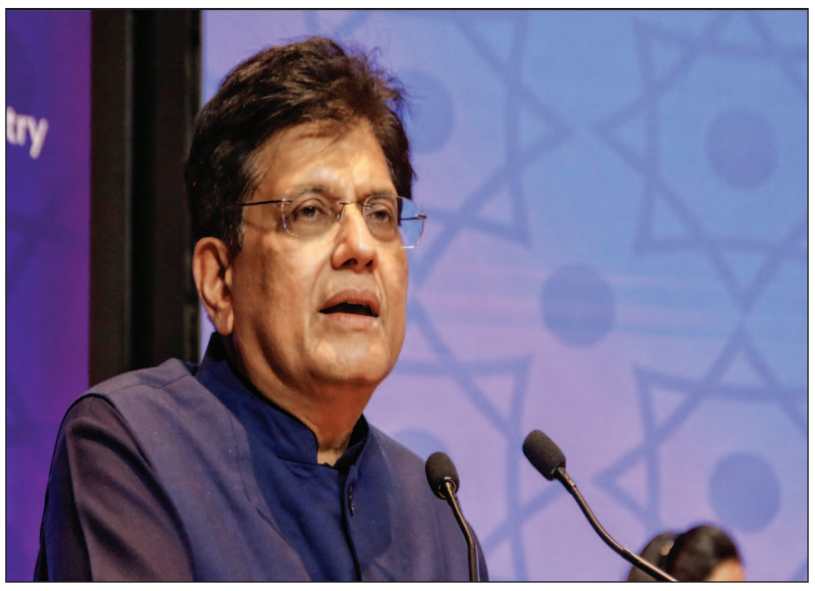

रूस का बड़ा फैसला, अमेरिका के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता किया समाप्त

मॉस्को, एजेंसी। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अब रूस और अमेरिका के बीच हुए न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी न्यू स्टार्ट समझौते से जुड़ी कोई बाध्यता दोनों देशों पर नहीं रह गई है। मंत्रालय का मानना है कि समझौते की अवधि खत्म होने के बाद अब दोनों पक्ष इसके नियमों को मानने के लिए मजबूर नहीं हैं।

रूस के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि परमाणु हथियारों की तय सीमा को समझौते की समाप्ति के बाद भी स्वेच्छा से बनाए रखने के रूस के प्रस्ताव पर अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक और साफ जवाब नहीं मिला है। यह समझौता 5 फरवरी को खत्म हो चुका है।

मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा हालात में रूस यह मानता है कि न्यू स्टार्ट समझौते से जुड़े सभी पक्ष अब इस समझौते की शर्तों और आपसी घोषणाओं से मुक्त हो चुके हैं। इसमें समझौते के मुख्य नियम भी शामिल हैं। अब दोनों देश अपने अगले कदम खुद तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

रूस ने यह भी कहा कि यदि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी नए खतरे का सामना करना पड़ा, तो वह उससे निपटने के लिए कड़े सैन्य और तकनीकी कदम उठाने के लिए तैयार है। समाचार एंजेसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि अगर सही हालात बनते हैं, तो रूस रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत के लिए भी तैयार है।

न्यू स्टार्ट समझौता रूस और अमेरिका के बीच वर्ष 2010 में हुआ था। इसका उद्देश्य दोनों देशों के परमाणु हथियारों और उन्हें ले जाने वाले साधनों की संख्या को सीमित करना था। यह समझौता 5 फरवरी 2011 से लागू हुआ था। पहले इसकी अवधि 10 साल की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 5 फरवरी 2026 तक कर दिया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सितंबर 2025 में कहा था कि अगर अमेरिका ऐसे कदम नहीं उठाता जिससे रणनीतिक संतुलन बिगड़े, तो रूस समझौते की मूल सीमाओं का पालन समाप्ति के बाद भी एक साल तक करता रहेगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में कहा था कि उन्हें इस समझौते के खत्म होने की ज्यादा चिंता नहीं है और उन्हें उम्मीद है कि दोनों देश किसी नए समझौते पर पहुंच सकते हैं। गौरतलब है कि न्यू स्टार्ट समझौता ही अब रूस और अमेरिका के बीच हथियार नियंत्रण से जुड़ा आखिरी बड़ा समझौता बचा है। इससे पहले अमेरिका वर्ष 2019 में इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी से बाहर निकल चुका है।

परमाणु हथियारों पर 50 साल से लगा पहरा हटा, अमेरिका–रूस के बीच 'न्यू स्टार्ट' संधि आज से खत्म

वॉशिंगटन, एजेंसी। वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से आज का दिन बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक है। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाली आखिरी बड़ी बाधा आज यानी 5 फरवरी 2026 को खत्म हो गई है। 'न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी' की अवधि समाप्त होने के साथ ही, पिछले लगभग 50 सालों में यह पहला मौका है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों के रणनीतिक हथियारों—जैसे अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें और बमवर्षक विमानों—पर कोई भी कानूनी या बाध्यकारी सीमा नहीं बची है। विशेषज्ञों ने इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरे की घंटी बताया है।

रूस का ऐलान- अब हम किसी बंधन में नहीं

संधि की मियाद पूरी होते ही रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने वाली किसी भी शर्त से बंधा नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि अमेरिका ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया, जिसमें संधि की शर्तों को अगले 12 महीने तक जारी रखने की बात कही गई थी। मंत्रालय ने खेद जताते हुए कहा कि उनकी बातों को जानबूझकर अनदेखा किया गया, इसलिए अब वे इस संधि के तहत किसी भी दायित्व या पारस्परिक घोषणाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। रूस ने इसे अमेरिका द्वारा सहयोग न करने का परिणाम बताया है।

क्या थी न्यू स्टार्ट संधि और इसका इतिहास

इस ऐतिहासिक समझौते की नींव 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने रखी थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन विनाशकारी रणनीतिक परमाणु हथियारों की तैनाती को सीमित करना था जो पल भर में प्रमुख सैन्य और औद्योगिक ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। यह संधि 2011 में लागू हुई थी और इसे 2021 में जो बाइडेन प्रशासन ने पांच साल के लिए बढ़ाकर 2026 तक कर दिया था। परमाणु नियंत्रण की यह कोशिश शीत युद्ध के समय से चली आ रही थी, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में साल्ट (स्ररुञ्ज) समझौते से हुई थी और बाद में स्टार्ट-1, स्टार्ट-2 और मॉस्को संधि के जरिए हथियारों में कटौती की गई थी। लेकिन आज न्यू स्टार्ट के खत्म होने के साथ ही यह पुराना ढांचा पूरी तरह ढह गया है।

संयुक्त राष्ट्र और विशेषज्ञों ने जताई गहरी चिंता

इस संधि के खात्मे को संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक ₹गंभीर क्षण₹ करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने चेतावनी दी है कि आधी सदी से अधिक समय में दुनिया पहली बार ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है, जहां परमाणु महाशक्तियों पर कोई लगाम नहीं है। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जोखिम दशकों में सबसे उच्चतम स्तर पर है। वहीं, पोप लियो ने भी दोनों देशों से अपील की थी कि वे भय और अविश्वास की राजनीति को छोड़कर साझा वैश्विक हितों को प्राथमिकता दें। सुरक्षा विशेषज्ञों, जैसे फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के मैट कोर्डा का मानना है कि अब दोनों देश अपनी तैनात परमाणु क्षमताओं को दोगुना तक बढ़ा सकते हैं, जिससे चीन जैसे देशों पर भी परमाणु विस्तार का दबाव बढ़ेगा।

अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 90त्न हथियार

मौजूदा समय में परमाणु शक्ति का संतुलन बेहद नाजुक है। जनवरी 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, रूस के पास 4,309 और अमेरिका के पास 3,700 परमाणु वारहेड्स हैं। यह दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90 प्रतिशत से अधिक है। संधि खत्म होने के बाद अब दोनों देशों के लिए मिसाइलों की संख्या बढ़ाने और सैकड़ों अतिरिक्त रणनीतिक वारहेड्स तैनात करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वे भविष्य में चीन को शामिल करते हुए किसी बेहतर समझौते पर विचार कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल दुनिया बिना किसी परमाणु सुरक्षा कवच के एक नए और खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है।

पाकिस्तान के कपास निर्यात पर मंडराया संकट, ईयू और अमेरिका से ट्रेड डील के बाद भारत को बढ़त

इस्लामाबाद, एजेंसी। भारत द्वारा यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ की गई अहम व्यापारिक डील से पड़ोसी देश पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। खास तौर पर इन समझौतों का सीधा असर पाकिस्तान के कपास और वस्त्र निर्यात पर पड़ सकता है। पाकिस्तान के उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात में जल्द सुधार नहीं हुआ, तो वैश्विक बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति कमजोर हो सकती है।

भारत ने जहां यूरोपीय संघ के साथ बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति जताई है, वहीं अमेरिका के साथ नई ट्रेड डील के तहत भारत पर लगाए गए आयात शुल्क में भी बड़ी कटौती की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लागू 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने का ऐलान किया है।

पाकिस्तान के उद्योग जगत में बढ़ी चिंता

ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, कॉटन जिनर्स फोरम के अध्यक्ष एहसानुल हक ने मौजूदा हालात को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यदि सरकार ने कपास और कपड़ा उद्योग को राहत देने के लिए तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए, तो पाकिस्तान के निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। उन्होंने चेताया कि नीतिगत फैसलों में देरी से क्षेत्रीय स्तर पर लागत का अंतर और बढ़ेगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में पाकिस्तान की पकड़ कमजोर होती जाएगी।

भारत को क्यों मिल रही है बढ़त

उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, हालात तब और चुनौतीपूर्ण हो गए जब यूरोपीय संघ ने भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18 से 25 प्रतिशत के दायरे में कर दिया है। इसके विपरीत, पाकिस्तान के उत्पादों को अमेरिकी बाजार में अब भी करीब 19 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। जानकारों का कहना है कि इस शुल्क अंतर का सीधा लाभ भारत को मिलेगा।

सरकार से राहत पैकेज की मांग

कॉटन जिनर्स फोरम ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि देश में उत्पादन लागत को पड़ोसी देशों के बराबर लाया जाए, ताकि निर्यात के मोर्चे पर प्रतिस्पर्धा बनी रहे। इसके अलावा लंबे समय से लंबित रिफंड जारी करने या उन्हें सुपर टैक्स देनदारियों के साथ समायोजित करने की भी मांग की गई है।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील से नई राह

सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की। भारत और अमेरिका के बीच यह व्यापार समझौता करीब एक साल से चर्चा में था। अमेरिका की ओर से इस डील में यह शर्त भी रखी गई है कि भारत रूस से तेल आयात को बंद करेगा।

ईयू के साथ 'मदर ऑफ ऑल डील्स'

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को व्यापक रूप से 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है। दोनों पक्षों ने संकेत दिए हैं कि इस समझौते को इसी वर्ष लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, समझौते के लागू होते ही भारत के करीब 99 प्रतिशत निर्यात को यूरोपीय संघ में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे आने वाले पांच वर्षों में भारत के निर्यात के दोगुना होने की संभावना जताई जा रही है।

केरल में भाजपा के वरिष्ठ नेता पर FIR, घोटाले में ए एन राधाकृष्णन का नाम आया

बंगलूरू, एजेंसी। केरल पुलिस ने कथित सीएसआर फंड घोटाले में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ए एन राधाकृष्णन समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया है।

यह घोटाला सीएसआर फंड का इस्तेमाल करके लोगों को आधे दाम पर स्कूटर और लैपटॉप देने का झूठा वादा करके कथित तौर पर धोखा देने से जुड़ा है। इस मामले में, एक महिला की शिकायत पर भाजपा नेता ए एन राधाकृष्णन समेत चार लोगों के खिलाफ IPC की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत प्रथामिकी दर्ज की गई है। महिला ने शिकायत में कहा है कि उससे 63,500 रुपये लेने के बाद भी स्कूटर नहीं दिया गया।

एनजीओ को दिया था पैसा

महिला की शिकायत के अनुसार, यह पैसा मई 2024 में सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड ग्रोथ ऑफ द नेशन नाम के एक एनजीओ के प्रतिनिधियों को दिया गया था। पुलिस ने जानकारी दी कि भाजपा नेता पर महिला के बयान के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला ने बताया है

गढ़चिरौली मुठभेड़ में अब तक तीन नक्सली ढेर, घायल जवान ने तोड़ा दम

गढ़चिरौली, एजेंसी। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में दो और नक्सलियों के मारे की खबर सामने आई है। जबकि मुठभेड़ के दौरान घायल हुए एक सी-60 जवान ने दम तोड़ दिया है। नक्सलियों के खिलाफ यह अभियान तीन दिन पहले शुरू किया गया था, जिसमें अब तक तीन नक्सलियों को मार गिराया है।

पुलिस के मुताबिक एसडीपीओ भामरागड के नेतृत्व में 14 सी-60 यूनिटों को शामिल करते हुए यह अभियान मंगलवार (03 फरवरी) को शुरू किया गया। ऑपरेशन गढ़चिरोली-नारायणपुर (छत्तीसगढ़) सीमा पर फोडेवाड़ा गांव के पास माओवादियों की कंपनी नंबर 10 के कैडरों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद चलाया गया। इस दौरान मजवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग की गई।

दो नक्सली शिविर नष्ट

इस बीच पुलिस ने बुधवार को दो नक्सली शिविरों का भंडाफोड़ किया। इसके बाद गुरुवार सुबह अच्छी तरह से पकड़ने जमाने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की चार और सी-60 यूनिट व क्यूएटी की एक यूनिट तैनात की गई।

तीन शव बरामद, भारी हथियार भी मिले

पुलिस के मुताबिक गुरुवार को एक नक्सली का शव, एक एके-47 राइफल और एक सेल्फ-लोडिंग राइफल (एसएलआर) बरामद की गई। उन्होंने बताया कि दो और नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें एक महिला का शव भी शामिल है। इसके साथ ही मौजूदा अभियान में मारे गए नक्सलियों की कुल संख्या तीन हो गई है।

घायल जवान ने तोड़ा दम, एक खतरे से बाहर

तीनों नक्सलियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इस बीच नक्सल विरोधी अभियान में घायल होने के बाद सी-60 जवान दीपक चिन्ना मदावी (38), जिनको पहले भामरागड ले जाया गया था, उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक अन्य घायल जवान, जोगा मदावी को भी एयरलिफ्ट करके भामरागड ले जाया गया है। पुलिस ने बताया कि वह खतरे से बाहर हैं और उन्हें जल्द ही गढ़चिरोली ले जाया जाएगा।

कांग्रेस ने पार्टी के संयुक्त सचिव को भेजा नोटिस, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी। असम में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व राज्य पार्टी अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने आरोप लगाया है कि संयुक्त सचिव पंकज सैकिया ने उनके बारे में मीडिया में कथित तौर पर अनुचित टिप्पणी की। उन्होंने संयुक्त सचिव पंकज सैकिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

मीडिया में की अनुचित टिप्पणी

पार्टी की असम इकाई के महासचिव (संगठन) बिपुल गोगोई ने गुरुवार को जारी नोटिस में सैकिया से 24 घंटे के भीतर अपना जवाब देने को कहा है। शुक्रवार को मीडिया के साथ साझा किए गए नोटिस में कहा गया है, 'असम पीसीसी के माननीय अध्यक्ष गौरव गोगोई के संज्ञान में आया है कि आपने पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और अभियान समिति के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा से संबंधित मामलों पर मीडिया में अनुचित टिप्पणी की है।'

24 घंटे में स्पष्टीकरण देने का अनुरोध

उन्होंने नोटिस में आगे कहा ₹निर्देशानुसार, आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि पार्टी अनुशासन के उपरोक्त उल्लंघन के लिए आपके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। आपसे 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया जाता है'

'दो दीवाने सहर में' का ट्रेलर रिलीज, रोमांटिक फिल्म में जची मृणाल और सिद्धांत की शानदार केमिस्ट्री

मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'दो दीवाने सहर में' का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। ट्रेलर में दो प्रेमियों की कहानी देखने को मिलती है। दोनों की पसंद अलग है, लेकिन फिर कैसे दोनों एक-दूसरे के प्यार में पड़ते हैं और अंत में उनकी प्रेम कहानी किस मोड़ पर पहुंचती है, ये फिल्म में देखने को मिलेगा।

ट्रेलर की शुरुआत में मृणाल (रोशनी) और सिद्धांत (शशांक) के किरदार अपनी-अपनी आदतों और पसंद के बारे में बताते हैं। इसके बाद ट्रेलर में देखने को मिलता है कि दोनों की शादी की बात होती है, जहां शशांक के घरवाले रोशनी के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। दोनों के पेरेंट्स दोनों को शादी करने के लिए कहते हैं और कैसे बात करना है ये बताते हैं। शशांक 'श' को 'स' कहता है, जिसके चलते उसे पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शादी के लिए रोशनी शशांक को मना कर देती है। लेकिन बाद में दोनों एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके बीच प्यार पलने लगता है। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि दोनों फिर अलग हो जाते हैं। अंत में क्या होता है, ये जानने के लिए फिल्म देखनी पड़ेगी।

1 मिनट 58 सेकंड के इस ट्रेलर में अरेंज मैरिज, प्यार और प्रोफेशनल लाइफ सभी पर बात की गई है। एक ओर जहां दिखाया जाता है कि प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह की दिक्कतें आती हैं और मृणाल का किरदार जैसे हो, वैसे रहने की बात करता है। वहीं दूसरी ओर अरेंज मैरिज के लिए कैसे घर वाले दबाव बनाते हैं और कहते हैं, वो भी दिखाया गया है। ट्रेलर से फिल्म की कहानी के बारे में काफी हद तक पता चलता है। फिल्म के गाने पहले से ही पसंद किए जा रहे हैं। अब देखने है कि फिल्म दर्शकों को कितना प्रभावित कर पाती है।

रवि उदयवार द्वारा निर्देशित 'दो दीवाने सहर में' 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी के अलावा नवीन कौशिक, इला अरुण, जॉय सेनगुप्ता और आयशा रजा भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए हैं।

आलिया भट्ट ने दृश्यम 2 निर्देशक अभिषेक पाठक से मिलाया हाथ, होगा बड़ा धमाका

अभिनेत्री आलिया भट्ट आगामी फिल्म एल्फा को लेकर चर्चा में हैं जो इसी साल रिलीज होगी। खबर है कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए कमर कस ली है। अभिनेत्री एक हाई-वोल्टेज ड्रामा प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रही हैं, जिसके लिए उन्होंने निर्देशक अभिषेक पाठक से हाथ मिलाया है। इस फिल्म का शीर्षक हाउसवाइफ होगा और आलिया को एक विवाहित महिला का किरदार निभाते देखा जाएगा। बता दें, अभिषेक ने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 का निर्देशन किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, हाउसवाइफ नाम वाली इस फिल्म की कहानी एक विवाहित जोड़े के इर्द-गिर्द घूमेगी जिसमें आलिया एक गृहणी के किरदार में होंगी। फिल्म में मुख्य पुरुष किरदार के लिए राजकुमार राव से बातचीत चल रही है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी दिलचस्प तो दिखाई है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। अगर राजकुमार हामी भरते हैं, तो पहली बार फिल्मी पर्दे पर आलिया और राजकुमार की जोड़ी दिखाई देगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आलिया हाउसवाइफ में सिर्फ अभिनय नहीं करेंगी, बल्कि अपनी कंपनी एटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस और पैनोरमा स्टूडियोज के सहयोग से सह-निर्माता भी होंगी। फिल्म की शूटिंग अगस्त या सितंबर, 2026 के बीच शुरू होने की संभावना है। तब तक निर्देशक दृश्यम 3 की शूटिंग पूरी कर लेंगे जिसके जरिए अजय की दमदार वापसी होगी। फिलहाल, आलिया लव एंड वार में व्यस्त चल रही हैं, जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी हैं।

इंडस्ट्री को लेकर एआर रहमान की टिप्पणी पर करन सिंह ने जताई आपत्ति, कहा– 'यह बयान देश की छवि को खराब करते हैं'

बीते दिनों एआर रहमान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई। अब संविधान सम्मान मंच के पदाधिकारी करन सिंह ने इस पर रिएक्शन दिया है।

लोकप्रिय म्यूजिक कंपोजर एवं डायरेक्टर एआर रहमान बीते दिनों बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर की गई एक टिप्पणी को लेकर काफी विवादों में रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड को कथित तौर पर 'सांप्रदायिक' बताया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हुई। रहमान ने बाद में वीडियो जारी कर सफाई पेश की थी कि उनका ऐसा मतलब नहीं था। हाल ही में संविधान सम्मान मंच के पदाधिकारी करन सिंह ने बातचीत में रहमान की टिप्पणी पर आपत्ति जाहिर की है। जानिए उन्होंने क्या कहा?

एआर रहमान भारत को अस्थिर क्यों बताते हैं?

करन सिंह ने सबसे पहले एआर रहमान को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा, 'सबसे पहले तो यह समझ ही नहीं आया कि एआर रहमान अचानक ऐसी सांप्रदायिक बातें क्यों बोल रहे हैं। बाहर की मीडिया जैसे 'द गार्जियन' में वह भारत को साम्प्रदायिक रूप से अस्थिर बताते आ रहे हैं। 'छावा' जैसी फिल्म, जो छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य पर बनी है, उसे वह 'विभाजनकारी' कहते हैं। यह बयान सीधे सीधे देश की छवि को खराब करते हैं। यह गैर-जिम्मेदाराना हैं, भारत-विरोधी हैं और सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाने वाले हैं।

नेटफ्लिक्स ने पूछताछ क्यों नहीं की?

करन सिंह ने आगे कहा, 'सबसे बड़ी बात यह है कि नेटफ्लिक्स ने यह सब जानते हुए भी रहमान को अपने मंच पर बुलाया। कोई जांच नहीं, कोई सवाल नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति को 'अतिथि' बनाकर इंटरव्यू चलाना यानी उनकी बातों को और भी बढ़ावा देना। यह कैसे सही है।

नेटफ्लिक्स अपनी गाइडलाइन में खुद लिखता है कि देश की एकता के खिलाफ कोई कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा। तो फिर यह क्या था?'

'क्या नेटफ्लिक्स दंगे भड़काना चाहता है?'

उन्होंने सवाल उठाया, 'अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेटफ्लिक्स को ऐसा लग रहा है कि यह सब करके क्या वह देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काना चाहता है। भारत दुनिया के सबसे शांतिप्रिय देशों में से एक है। यहां हर धर्म के लोग साथ रहते हैं। फिर ऐसा कंटेंट लोगों की शांति भंग किसलिए कर रहा है।'

करन सिंह ने आगे कहा, 'सबसे बड़ी बात यह है कि नेटफ्लिक्स ने यह सब जानते हुए भी रहमान को अपने मंच पर बुलाया। कोई जांच नहीं, कोई सवाल नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति को 'अतिथि' बनाकर इंटरव्यू चलाना यानी उनकी बातों को और भी बढ़ावा देना। यह कैसे सही है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com